हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंकः मार्च–अप्रैल 2016

दिल्ली

ਦਿੱਲੀ

دلّی

होली मुबारक

देया रे मोहे भिजोया री
शाह निज़ाम के रंग में
कपड़े रंग के कुछ न होत है
या रंग में तन को डुबोया री
देया रे मोहे भिजोया री ।

।। अमीर खुसरो ।।

हो हो हो हो हो होरी ।
खेलत आज सुख प्रीति प्रगट भई,
उतहरि इतहि राधिका गोरी।
बाजत ताल मृदंग झाँझ डफ,
बीच–बीच बाँसुरि धुनि थोरी।।
गावत दै दै गारि परस्पर,
उत हरि दूत वृषभानु किसोरी।
मृगमद साख जवदि कुमकुमा,
केसरि, मिलै मिलै मथि घोरी ।।
गोपी ग्वाल गुलाल उड़ावत,
मत्त फिरैं रति–पति–मनु धोरी।
भरित रंग रति नागरि राजति,
मनहूँ उमंगि–बेला बल फोरी।।
छुटि गई लोकलाज कुल संका
गनति न गुरु गोपिनी कौ को री।
सूरदास सारदा विमलमति सो
अवलोकि भूलि भई भोरी।।

।। सूरदास।।

दिल्ली

अंक : मार्च–अप्रैल 2016

प्रधान सम्पादक
सज्जन सिंह यादव

विशेष निदेशक
संदीप मिश्र

सम्पादक
डॉ. पंकज श्रीवास्तव

सम्पादकीय सहयोग
नलिन चौहान
कंचन आजाद, विनोद गुप्ता
चन्दन कुमार, अमित कुमार
मनीष कुमार, उर्मिला बेनिवाल

छाया चित्र
सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

"दिल्ली" पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता
प्रधान सम्पादक
दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय
दिल्ली सरकार
खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
दूरभाष : 23819046, 23817926
फैक्स : 23814081
ई–मेल : delhidip@gmail.com

इस अंक में...

हिन्दी

केजरीवाल की 'सेवक सरकार' का एक साल, बेमिसाल! 2
उजाले की ओर 5
बुझने लगी प्यास 6
सुधरती सेहत 9
शिक्षा क्रांति 11
राहें नई–नई 15
यमुना तीरे 17
भ्रष्टाचार पर वार 18
रसोई में रंग 20
जनता है मालिक 22

पंजाबी

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ, ਬੇਮਿਸਾਲ ! 1
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਲ 4
ਬੁਝਣ ਲਗੀ ਪਿਆਸ 5
ਸੁਧਰਦੀ ਸਿਹਤ 8
ਸਿਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ 11
ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ 14

उर्दू

ایک سال، بے مثال کیجریوال کی خدمتگار سرکار کا 1
اجالے کی جانب 4
بجھنے لگی پیاس 5
سدھرتی صحت 7
تعلیمی کرانتی 9
راہیں نئی نئی 13

केजरीवाल की 'सेवक सरकार' का
एक साल, बेमिसाल!

14 फरवरी 2015 को पूरे देश ने एक चमत्कार घटित होते देखा था। आम लोगों के आंदोलन से राजनीतिक दल में तब्दील हुई एक पार्टी अभूतपूर्व बहुमत (70 में 67 सीट जीतकर) के साथ सरकार बना रही थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो रामलीला मैदान में उत्साह और उमंग हिलोरें ले रहा था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए रात दिन मेहनत की और जब पहले साल का हिसाब देने का वक्त आया तो उनके पास गिनाने के लिए ऐसा बहुत कुछ था जिसे देखकर जनता ने बहुत प्यार से कहा–'केजरीवाल बेमिसाल !'

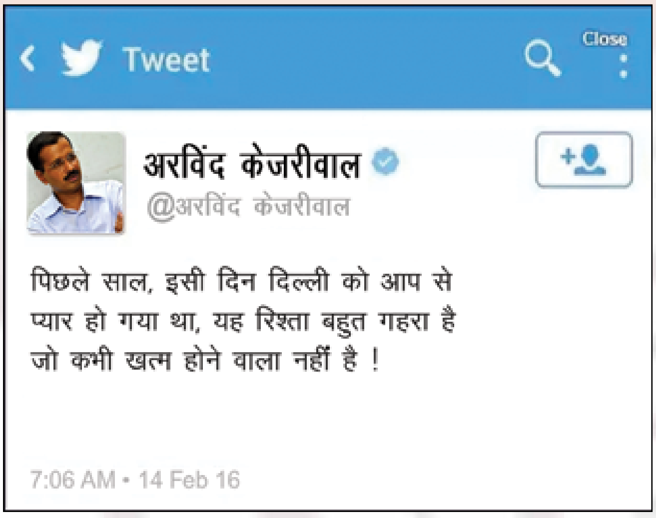

पहला साल, बेमिसाल!

14 फरवरी 2016 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री जनता को अपनी सरकार का हिसाब देने पहुँचे। उन्होंने साफ कहा कि जनता वोट देकर मालिक नहीं सेवक चुनती है। उसे सेवक से हिसाब लेने का पूरा हक है। सेवक का भी फर्ज है कि वह मालिक को समय–समय पर अपने कामकाज का लेखा–जोखा दे। उन्होंने इस खुशी के मौके पर 30 नवंबर तक पानी के बकाया बिलों को माफ करने की घोषणा की।

इस मौके पर केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने जनता के सवालों का सीधा जवाब दिया। इसके लिए कुछ फोन नंबर थे जिन पर लोगों ने सवाल पूछा और केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने जवाब दिए। कुछ चुने हुए सवाल यहाँ पेश हैं–

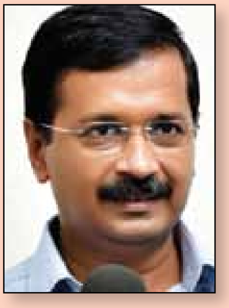

सवाल: भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर आम आदमी पार्टी सरकार का नाम लेते हैं, तो पुलिस और भड़क जाती है।

अरविंद केजरीवाल (सीएम): दुर्भाग्यवश पुलिस और एसीबी, दोनों ही दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। आप मुझे अपनी शिकायत की कॉपी दीजिए, उस शिकायत को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पास भेजूंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा। दिल्ली विधानसभा ने जनलोकपाल बिल पास कर दिया है और यह बिल केंद्र के पास है। अगर केंद्र मंजूरी दे दे तो फिर इस तरह की शिकायतों से आसानी से निपटा जा सकेगा।

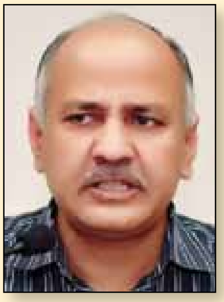

सवाल: आप सरकार ने 500 नए स्कूल शुरू करने की बात कही थी, इस मसले पर क्या कार्रवाई हुई है?

मनीष सिसोदिया (उप मुख्यमंत्री): इस साल 25 नए स्कूल शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही 200 स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 8,000 नए क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ 100 नए स्कूलों के लिए जमीन तलाशी गई है। जहां–जहां पर नए स्कूलों के लिए जमीन मिल रही है, वहां पर नए स्कूल बनाए जाएंगे।

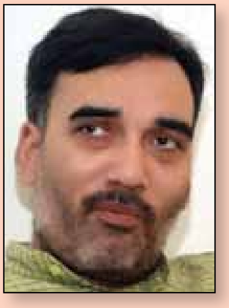

सवाल: ऑड–इवन स्कीम को लेकर क्या अनुभव रहे ?

गोपाल राय (परिवहन मंत्री): ऑड–इवन योजना का प्रयोग कई देशों में किया गया था, लेकिन वहाँ पर यह अभियान लोकप्रिय नहीं हो पाया। दिल्ली में जनता ने इस अभियान को बहुत पसंद किया और अब 15 अप्रैल से फिर से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। ऑड–इवन योजना के दौरान जहां प्रदूषण स्तर में 20 से 24 प्रतिशत तक की कमी आई, वहीं दिल्लीवालों को जाम से भी मुक्ति मिली।

पहला साल, बेमिसाल!

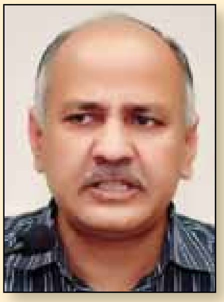

सवालः दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने 2010 में हुए टीजीटी (सोशल साइंस) की परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं किया। कई उम्मीदवार अब अधिकतम उम्र सीमा पार कर गए हैं।

मनीष सिसोदिया (उप मुख्यमंत्री): बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि अप्रैल तक परिणाम आ जाएगा। इसके अलावा मई तक ज्यादातर परिणाम आ जाएंगे। डीएसएसएसबी की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी, ताकि जल्द परिणाम आ जाए। परिणाम आने में देरी के चलते सरकार को भी परेशानी होती है। स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन परिणाम आने में देरी के चलते भर्ती नहीं हो रही है।

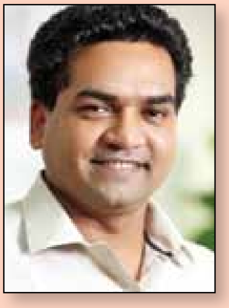

सवालः यमुना को पर्यटन से जोड़ने के लिए सरकार की क्या योजना है?

कपिल मिश्रा (पर्यटन मंत्री): यमुना को लेकर सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। यमुना किनारे जहां–जहां साफ पानी है, वहां पर बोटिंग शुरू की गई है। यमुना आरती भी शुरू की गई है। आने वाले समय में यमुना को निश्चित तौर पर पर्यटन से जोड़ा जाएगा।

सवालः खाने पीने में मिलावट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है?

सत्येंद्र जैन (स्वास्थ्य मंत्री): खाने–पीने में मिलावट रोकने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला बनाने जा रही है। अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इंटरनेशनल फूड सेफ्टी लैब में खाने की चीजों में मिलावट को पकड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। नई प्रयोगशालाओं में आधुनिक सुविधाएं होंगी और उच्च स्तरीय टेस्ट किए जा सकेंगे। इससे खाने–पीने की चीजों में मिलावट को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। अभी मौजूदा प्रयोगशालाएं उतनी कारगर साबित नहीं हो रही हैं।

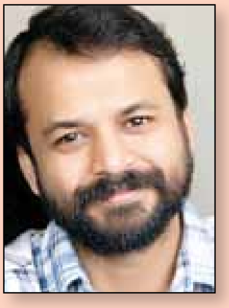

सवालः आम आदमी कैंटीन का प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है?

आशीष खेतान (उपाध्यक्ष, दिल्ली डायलॉग कमीशन): दिल्ली डायलॉग कमीशन ने आम आदमी कैंटीन की पॉलिसी तय की है। इस साल के आखिर तक 70 से 80 कैंटीन शुरू हो जाएंगी। दिल्ली युनिवर्सिटी इलाके में भी कैंटीन होगी। एक साथ बड़े पैमाने पर कैंटीन शुरू होंगी।

उजाले की ओर...

सस्ती बिजली

आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बिजली बिल आधे करने का वादा पूरा किया गया। 400 युनिट तक प्रति माह बिजली की खपत करने वाले सभी उपभोक्तों को यह छूट मिली। दिल्ली के करीब 90 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला। सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। दिल्ली सस्ती बिजली के मामले में तीसरा सबसे सस्ता राज्य है। यही नहीं बिजली कंपनियो के दबाव के बावजूद सरकार ने बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी।

लोड शेडिंग बेहद कम

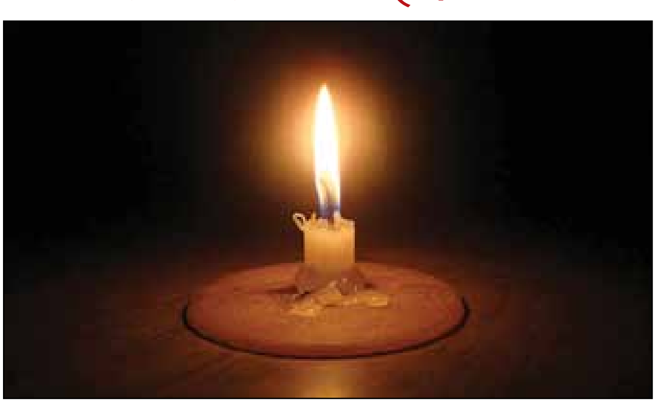

बिजली वितरण प्रक्रिया की सतत निगरानी की गई। इसकी वजह से लोड शेडिंग केवल 0.14 फीसदी रह गई जो पिछले साल की तुलना में 73 फीसदी कम थी। दिल्ली के इतिहास में इतनी कम लोड शेडिंग कभी नहीं हुई। दिल्ली वालों को इससे काफी राहत मिली।

लोडशेडिंग की शिकायत के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉलसेंटर स्थापित किया गया। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम्स) को निर्देश दिया गया कि किसी इलाके में लोड शेडिंग एक वक्त में एक घंटे से ज्यादा न हो और अगर इससे ज्यादा की जरूरत हो तो कारण स्पष्ट करते हुए लोगों को समय पर इसकी सूचना दी जाए।

सेटेलमेंट स्कीम

विवादित बिजली बिलों का मसला हल करने के लिए एक सेटेलमेंट स्कीम शुरू की गई। 30 अगस्त 2015 से शुरू हुई इस योजना से अब तक 55000 से अधिक उपभोक्ता लाभ उठा चुके हैं।

एलईडी बल्ब

ऊर्जा बचाओ अभियान के तहत दिल्ली में 93 रुपये की दर से करीब 40 लाख एलईडी बल्ब वितरित किये गये हैं। तीन साल की गारंटी वाले इन बल्ब के इस्तेमाल से दिल्ली में करीब 75 मेगावाट बिजली की बचत होगी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के मौजूदा बल्ब बदलकर एलईडी बल्ब लगाने की प्रक्रिय चल रही है। इससे करीब 50–60 मेगावाट बिजली की बचत होगी। अब तक साउथ एमसीडी इलाके में 1.25 लाख स्ट्रीट लाइट बदली जा चुकी हैं।

बिजली मीटर

बिजली मीटर के तेज चलने या गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत होने पर अब उसकी जाँच बिजली वितरण कंपनियों की प्रयोगशालाओं में नहीं होगी। अब इनकी जांच स्वतंत्र रूप से एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली की जनता बिजली मीटरों के तेज चलने की शिकायत काफी अरसे से कर रही थी। इसे बड़े घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा था। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान का वायदा किया था।

बुझने लगी प्यास...

पानी मुफ़्त

सरकार बनने के तुरंत बाद दिल्ली वालों से मुफ़्त पानी का वादा पूरा किया गया। 1 मार्च 2015 से हर महीने 20 हजार लीटर (करीब 700 लीटर प्रतिदिन) तक पानी के उपभोग पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इससे दिल्ली की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों समेत 8.99 लाख उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को मुफ़्त पानी देने का वायदा किया था तो विरोधियों ने इसे असंभव बताते हुए चुनावी झुनझुना करार दिया था। लेकिन सरकार ने न सिर्फ यह वायदा पूरा किया बल्कि इस मद में राजस्व की हानि भी नहीं होने दी।

बकाया बिल माफ़

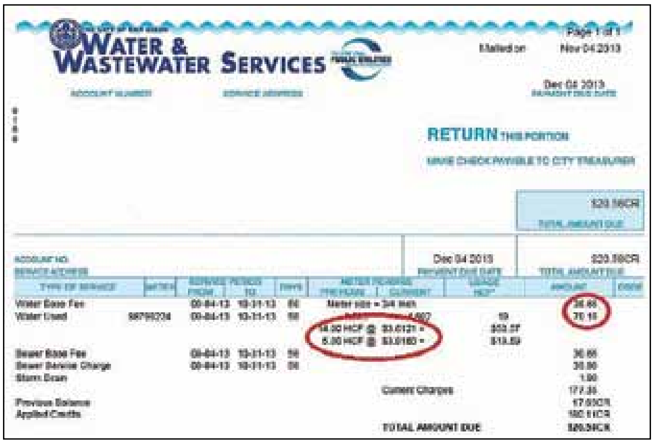

सरकार बनने की पहली वर्षगांठ पर 30 नवंबर 2015 तक बकाया सभी बिलों को माफ़ करने का एलान किया गया। उन सभी लोगों का बिल माफ़ हुआ जिनके घर पानी के मीटर लगे होंगे और वे चालू हालत में होंगे।

अनियमित कालोनियों को राहत

अनियमित कालोनियों को राहत दी गई। वाटर डेवलेपमेंट चार्ज को 440 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। इससे 1.2 लाख लोगों को सीधे फायदा पहुंचा। इस योजना को अगले छह महीने के लिए फिर से लागू कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। अनियमित कालोनियों में सीवर डेवलेपमेंट चार्ज 494 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जाता था। इसमें करीब 80 फीसदी की कमी करते हुए इसे सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया।

अपनी पसंद के मीटर

तय मानकों वाले पानी के मीटर बेचने के लिए तीन कंपनियों को अनुमति दी गई है। पांच साल की गारंटी वाले ये नये मीटर धूल–मिट्टी से खराब नहीं होते। लोग अपनी मर्जी से इनमें से किसी भी कंपनी का मीटर खरीद सकते हैं।

कनेक्शन लेना सस्ता

पानी के अवैध कनेक्शन को वैध करने की नीति उदार बनाई गई। पहले इसके लिए लोगों को 14000 रुपये देने पड़ते थे जिसे घटाकर 3310 रुपये कर दिया गया।

पानी के सीमित उपभोग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को घरेलू श्रेणी में लाया गया।

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

2011 से बनकर तैयार द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने 1 मार्च 2015 से काम करना शुरू कर दिया गया। 50एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) क्षमता वाले इस प्लांट के शुरू हो जाने से द्वारका उपनगर, नजफगढ़, दौलतपुर, उजवा और आसपास के इलाकों के साढ़े 13 लाख निवासियों को लाभ हुआ।

2002 में बने बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने 21 अप्रैल 2015 से काम करना शुरू किया। 20 एमजीडी क्षमता वाले इस संयंत्र से बवाना, नरेला, सनलोथ और आसपास के ग्रामीण इलाकों के करीब छह लाख निवासियों को लाभ हो रहा है। ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 7 एमजीडी से 20 एमजीडी हुई।

नई पाइपलाइन

एक साल में दिल्ली में 136 किलोमीटर नई पाइप लाइन बिछाई गई। साथ ही 148 किलोमीटर की जंग लगी पुरानी पाइप लाइन बदली गई ताकि दूषित जलापूर्ति न होने पाए।

लीकेज रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। पानी की किल्लत वाले इलाकों में 78 अतिरिक्त टैंकर लगाये गये हैं।

राजस्व बढ़ा

दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं की तादाद बढ़कर 19.58 लाख हो चुकी है। हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त देने के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले, दिल्ली जल बोर्ड को इस वर्ष फरवरी के पहले हफ्ते तक 178 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व मिला।

सुधरती सेहत...

दवा और जाँच मुफ़्त

1 फरवरी 2016 से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सारी दवाएँ मुफ़्त मिल रही हैं। डाक्टर जो भी दवा लिखते हैं उन्हें हर हाल में उपलब्ध कराना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था की निगरानी और दवाओं की सतत उपलब्धता के लिए एक मोबाइल एप भी बनाया गया है। एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड की भी निःशुल्क व्यवस्था है।

पॉली क्लीनिक

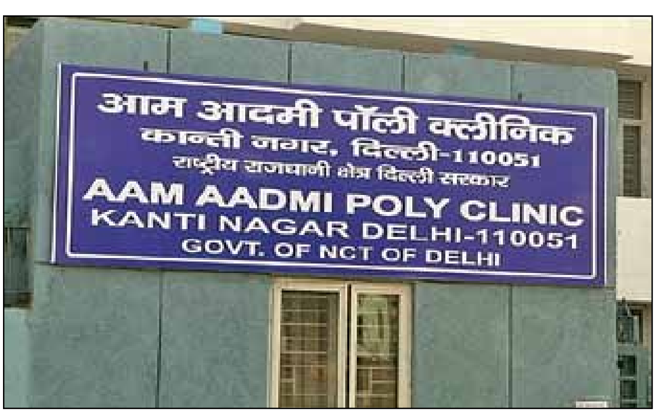

दिल्ली के बड़े अस्पतालों पर बोझ खत्म करने और घर के आसपास मरीज को समय पर जाँच कराने की सुविधा के लिए दिल्ली के अलग–अलग इलाकों में 22 पॉली क्लीनिक खोले गए हैं। हर क्लीनिक मे औसतन 1200 मरीज रोज पहुँच रहे हैं। साल के अंत तक पूरी दिल्ली में ऐसे 150 पॉली क्लीनिक शुरू हो जाएंगे।

मोहल्ला क्लीनिक

पीरागढ़ी के पंजाबी पुनर्वास बस्ती में पहला मोहल्ला क्लीनिक शुरू हो गया है। वहां दो सौ मरीज रोज देखे जाते हैं जिन्हें डाक्टरी परामर्श, दवायें और जांच सुविधा मुफ्त मे उपलब्ध होती है। बुराड़ी और मंडावली में भी मोहल्ला क्लीनिक बनकर तैयार हैं। मोहल्ला क्लीनिक सिर्फ 20 लाख रुपये की लागत में बनकर तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक का टेंडर जारी हो गया है।

मोहल्ला क्लीनिक के प्रयोग को देश ही नहीं, दुनिया भर में बेहद उत्सुकता से देखा जा रहा है। मोहल्ला क्लीनिक को बीमारियों की रोकथाम में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही अपने मोहल्ले में प्रशिक्षित डॉक्टर के मौजूद होने पर लोग झोलाछाप डाक्टरों के चंगुल में फँसने से भी बच सकेंगे।

पहला साल, बेमिसाल!

बढ़ेंगे मरीज़ों के बेड

तमाम अस्पतालों में मरीज़ों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 2017 के दिसंबर तक दिल्ली के अस्पतालों में मरीज़ों के लिए 20000 बेड उपलब्ध होंगे।

यह संख्या अभी 10000 है। इसके अलावा 70 फीजियोथेरेपी और 250 डेंटल क्लीनिक भी खोले जाएंगे।

हेल्थ कार्ड

जल्द ही दिल्ली के लोगों के हेल्थकार्ड बनेंगे। इस स्कीम के तहत दिल्ली के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी डेटा रिकार्ड किया जाएगा।

पूरा हेल्थ सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होगा। डॉक्टरों को आसानी से मरीज का रिकार्ड तुरंत अपने कंप्यूटर पर दिख जाएगा तो इलाज में आसानी होगी।

डॉक्टरों को राहत

डॉक्टरों को तमाम व्यवस्था संबंधी काम की निगरानी के बोझ से मुक्त किया जाएगा ताकि वे मरीजों के इलाज पर ध्यान दे सकें। इसके लिए अस्पतालों में मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे।

नए अस्पताल

सरकार ने पांच नए अस्पतालों के लिए मादीपुर, नांगलोई, सरिता विहार, सिरसपुर और विकासपुरी में जगह फाइनल कर दी है। इसके लिए 10 और अस्पतालों के लिए डीडीए से जगह माँगी गई है।

पुराने अस्पतालों की हालत को इस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह प्राइवेट अस्पतालों से कम न लगें।

शिक्षा क्रांति...

21 नये स्कूल, 200 स्कूलों के बराबर कमरे

दिल्ली में 21 नये स्कूल बनकर तैयार हो गये हैं जहाँ जुलाई 2016 से पढ़ाई शुरू होगी। 63 नये स्कूलों पर काम जारी है। पीडब्ल्यूडी 25 और नये स्कूल बना रहा है। ग्राम सभा जमीन के 38 प्लॉट पर नये स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा मौजूदा स्कूलों में 8,000 नये कमरे जोड़े जा रहे हैं। इनमें क्लासरूम, लैब, बहुउद्देशीय हॉल आदि हैं। औसतन एक स्कूल में 40 कमरे होते हैं। इस तरह तकरीबन 200 नये स्कूलों के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले साल ही तैयार हो गया। इसके अलावा पांच अन्य स्कूलों में डबल शिफ्ट की अनुमति दे दी गई है।

10 हज़ार स्थायी शिक्षक

दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए 10,000 नये स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात को 40:1 तक लाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस संबंध में गेस्ट शिक्षकों से किया गया वादा पूरा किया जा रहा है। उन्हें आयु सीमा में छूट दी जा रही है। साथ ही उन्हें अनुभव के वर्ष के हिसाब से वेटेज भी दिया जा रहा है। अगर किसी गेस्ट टीचर ने शैक्षिक सत्र 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के दौरान हर सत्र में कम से कम 120 दिन शिक्षण कार्य किया है, उसे 2.25 फीसदी का वेटेज मिल जाएगा।

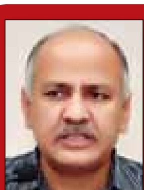

दिल्ली के लोग जल्द ही सरकारी स्कूलों में विश्वस्तरीय पढ़ाई–लिखाई होते देखेंगे।

–मनीष सिसोदिया

पहला साल, बेमिसाल!

ऑनलाइन परीक्षा

दिल्ली में ऐसा पहली बार होगा जब इतने कम समय में 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भारत सरकार की मिनीरत्न इंटरप्राइजेट एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (एडसिल) ये ऑनलाइन एग्जाम लेगी।

स्कूलों में सीसीटीवी

सभी सरकारी स्कूलों के सभी कमरों, गलियारों इत्यादि में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो स्कूलों के सभी कमरों, लैब, गलियारों इत्यादि में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उप–मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जाकर इनका निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों ने बताया कि अब उनके सामान चोरी नहीं होते, वे क्लास में ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, शिक्षक पहले की तुलना में ज्यादा रेगुलर हो गए हैं। हर क्लास के बच्चों और शिक्षकों ने कहा कि सीसीटीवी लगना चाहिए।

स्कूलों में साफ़ सफ़ाई

साफ़–सफ़ाई के मामले में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। कई बड़े स्कूलों में भी केवल एक या दो सफ़ाईकर्मी होते थे जिससे पूरी व्यवस्था बदतर स्थिति में पहुंच गई थी। इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए। स्कूलों सफ़ाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार के नये टेंडर से अब हर स्कूल को कम से कम 4 सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे। एप के जरिये साफ़–सफ़ाई की स्थिति पर सरकार की ऑनलाइन नजर रहती है।

एस्टेट मैनेजर

हर स्कूल में हर पाली में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के सहयोग के लिए एक–एक एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति की जा रही है। यह शायद देश में पहली बार किया गया है कि स्कूलों में प्रधानाध्यापक की मदद के लिए एस्टेट

मैनेजर की व्यवस्था हो और उसकी नियुक्ति भी स्वयं प्रधानाध्यापक ही करे। एस्टेट मैनेजर एक मोबाइल एप के जरिये रोजाना अपने–अपने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति से शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों सहित उप–मुख्यमंत्री को भी अवगत करा रहे है।

प्रधानाचार्य को अधिकार

स्कूलों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए प्रधानाध्यापक स्वयं रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिनिस्ट्रयल कार्य के लिए नियुक्त कर सकेंगे। इससे शिक्षकों के ऊपर मिनिस्ट्रियल कार्य करने का अतिरिक्त बोझ कम हो जाएगा।

10 लाख तक का शिक्षा लोन

हॉयर, टेक्निकल और स्किल एजुकेशन के लिए अब दिल्ली सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन अपनी गारंटी पर दिला रही है। दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, स्किल सेंटर्स, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि में पढ़ाई के लिए लोन मिलता है। इस योजना में कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च के साथ–साथ किताबों, कंप्यूटर आदि के लिए भी लोन मिलता है। पहले स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन के लिए कीमती चीज गिरवी रखने या दूसरी गारंटी की जरूरत होती थी। लोन के लिए मां–बाप की प्रॉपर्टी या अन्य वित्तीय जमानत की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 लाख रुपये तक के लोन की गारंटी सरकार खुद ले रही है। साथ ही प्रोसेसिंग चार्ज, मार्जिन मनी, थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है।

अभिभावकों की भागीदारी

अभिभावकों की भागीदारी ने बदली स्कूलों की दशा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के जरिये पैरेंट्स की भागीदारी बढ़ाने से पूरी स्कूली व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव आया है। दिल्ली सरकार के सभी 1011 स्कूलों में एसएमसी मेंबर्स का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ जो ऐतिहासिक था। अभिभावकों की बाकायदा वोटर लिस्ट तैयार की गई। लाखों अभिभावकों ने एसएमसी सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग की। चुनाव के लिए बाकायदा नामांकन फार्म भरे गये। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति को अपने नामांकन फार्म के साथ 10 अभिभावकों के हस्ताक्षर कराना भी अनिवार्य किया गया था। शिक्षा विभाग ने इन चुनावों के लिए हर स्कूलों में बाकायदा ऑब्जर्वर तैनात किये। इससे अभिभावकों की भागीदारी स्कूल में बढ़ी है। वे साफ–सफाई से लेकर मिड डे मील की क्वालिटी तक में समय–समय पर नजर रखते हैं। देश में यह यह अपनी तरह का पहला प्रयास है।

गुणवत्ता के साथ शिक्षा

यह बहुत स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता गिरी है। बच्चों का साल दर साल पास कर दिया जाता है भले ही वो ठीक से सीख पाये हों या नहीं। बच्चे 9वीं में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको बुनियादी जानकारी भी नहीं होती। इसलिए दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में डेढ़ महीने का विशेष लर्निंग एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाया गया। इसका बहुत सकारात्मक असर दिखा है। अब बाकी राज्यों के लोग इस प्रोग्राम को समझना चाहते हैं ताकि वे अपने यहां भी इसे लागू कर सकें।

बदलाव के प्रयोग

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 54 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। "नो डिटेंशन" पालिसी खत्म करने का फैसला किया गया है ताकि कक्षा दस तक बिन पढ़े भी पहुंच जाने का सिलसिला थमे। निजी स्कूलों के मैनेजमेंट की मनमानी रोकने के तमाम कदम उठाये गये हैं। फिर चाहे मामला मैनेजमेंट कोटे का हो या मनमानी फीस का। सरकार अदालतों में भी इस मसले पर मजबूती से जनता के पक्ष में खड़ी हुई है।

खेल विश्वविद्यालय

सरकार ने दिल्ली में नई खेल संस्कृति विकसित करने का बीड़ा उठाया है। कोशिश की जा रही है कि वार्ड स्तर से लड़के–लड़कियों में खेलों के प्रति दिलचस्पी पैदा की जाए ताकि प्रतिभाओं को वक्त रहते पहचान लिया जाए और उन्हें जरूरी सुविधाएं देकर तराशा जाए। यही नहीं आगे चलकर प्रतिभाशाली छात्रों को खेलों में ही डिग्री हासिल हो जाए ताकि उनके करियर की राह में बाधा न आये। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 'स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी" स्थापित करने की घोषणा की है।

"हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन व मनमानी फ़ीस का धंधा बंद हो जाए। प्राइवेट स्कूलों के लिए कानून बनाया है जो केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए पड़ा है और एक आदेश दिया है जिसे प्राइवेट स्कूल अदालत में ले गए है ।"

–मनीष सिसोदिया

राहें नई-नई...

ऑड-इवन

दिल्ली सरकार ने ऑड–इवन जैसा अभिनव प्रयोग करके एक ऐतिहासिक शुरुआत की। देश में पहली बार ऐसा प्रयास हुआ जिसके सकारात्मक नतीजे आये। 1 जनवरी 2016 से 15 जनवरी के बीच हुए इस प्रयोग की जनता ने भरपूर सराहना की और इसका साथ दिया। प्रतिदिन करीब 10 लाख गाडियाँ सड़कों पर कम उतरीं जिससे प्रदूषण में कमी आई साथ ही जाम की समस्या से निजात मिली। जनता ने इस स्कीम को फिर से शुरू करने के पक्ष में राय दी है, जिस पर सरकार अमल करने जा रही है।

कार-फ्री डे

लोगों को प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए हर महीने की 22 तारीख को कार–फ्री डे का आयोजन किया जा रहा है। इसका एक मकसद लोगों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना भी है।

ऑटो चालकों को राहत

ऑटो रिक्शा और उनके चालकों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर की गईं। धारा 66/192 में संशोधन करके पुलिस से ऑटो जब्त करने का अधिकार ले लिया गया। अब काम खत्म करके घर जा रहे ऑटो चालकों का भी चालान नहीं किया जा सकता। एनसीआर (हरियाणा और उत्तर प्रदेश) के लिए चार हजार से ज्यादा ऑटो परमिट जारी किए गए।

ई-रिक्शा

ई–रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया निश्चित हुई। ई–रिक्शा पर सरकार 15000 रुपये की सब्सिडी देती है

जिसे जल्द ही 30000 रुपये कर दिया जाएगा। करीब 4600 ई–रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही "पूछो" एप फिर से लॉच किया गया। इससे नागरिकों को ऑटो और टैक्सी सुविधा पाना आसान हुआ। साथ ही ऑटो चलाने वालों की आय में भी इजाफा होगा।

बेहतर बसें

दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3200 मार्शल तैनात किये जा चुके हैं। अगले छह से 9 महीने में डीटीसी 1000 एसी बसें उतारेगा। इसके अलावा क्लस्टर श्रेणी में भी एक हजार बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली की सभी बसों में अगले छह महीने में सीसीटीवी/जीपीएस/वाईफाई सुविधा होगी। इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। टेंडर जल्द जारी होंगे।

नई सड़क

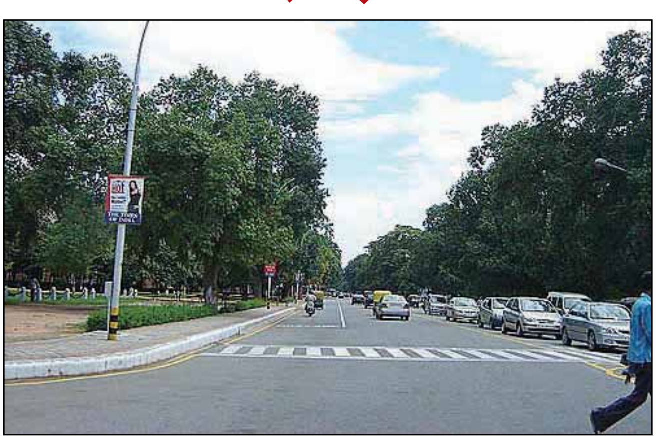

दिल्ली की सड़कों को को संवारने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों को री–डिजायन करने का फैसला किया है। सरकार इस पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार का जोर ऐसी सड़क बनाने का है जिन पर गाड़ीवालों के साथ–साथ पैदल और साइकिल वालों के लिए सुरक्षित हों, साथ ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भी असुविधा न हो।

इस प्रोजेक्ट के तहत ग्लास लिफ्ट, टॉयलट ब्लाक्स, सोलर स्ट्रीट लाइट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम भी लगाये जाएंगे। इसके अलावा रेहड़ी–पटरी वालों के लिए भी जगह होगी।

फिलहाल 10 सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है जहां जल्द ही रिडिजायन का काम शुरू हो जाएगा।

दो मंज़िला पुल

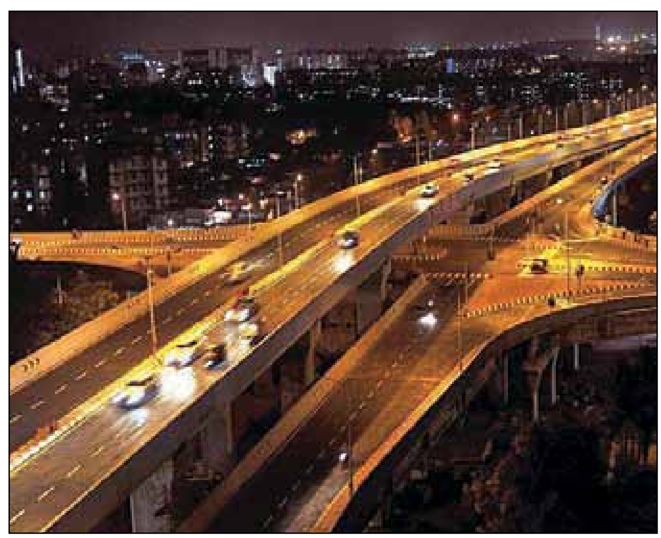

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की हालत सुधारने के लिए एक दूरदर्शी योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत दो मंज़िला एलिवेटेड रोड बनेंगी। एक रोड पर केवल बसें चलेंगी तो दूसरी पर कार।

ऊपर की मंज़िल पर बसें चलेंगी। बिना किसी बाधा के उनका सफर तेजी से पूरा होगा जिससे मेट्रो की तरह उनका भी टाइम–टेबल बन पाएगा। इन बसों की सुगम और सुखद यात्रा लोगों को आकर्षित करेगी कि वे निजी वाहन का इस्तेमाल न करें।

बीआरटी से निजात

दिल्ली सरकार ने वायदे के मुताबिक बीआरटी कॉरीडोर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। बीआरटी लोगों के लिए सहूलियत से ज्यादा परेशानी का सबब बन चुका था। आम लोगों को इसकी वजह से भारी जाम झेलना पड़ता था। इसे तोड़ने में करीब 12 करोड़ का खर्च आएगा। इसे डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत से 2008 में शीला दीक्षित सरकार ने बनवाया था। सरकार ने कहा है कि बीआरटी की गलतियों से सबक लेते हुए नए किस्म की डिजायन की सड़कें बनाई जाएंगी।

मेट्रो फेज़-4 को मंज़ूरी

दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज़–4 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने घोषणा की है कि फेज तीन का काम खत्म होते ही फेज चार का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत बाहरी दिल्ली के इलाकों को जोड़ने पर खास जोर होगा। डीएमआरसी इस संबंध में सरकार को प्रोजक्ट रिपोर्ट सौंप चुकी है। फेज चार में रिठाला से नरेला, जनकपुरी से आर.के. आश्रम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, तुगलकाबाद से ऐरोसिटी को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।

यमुना तीरे...

संकल्प की आरती

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यमुना का हाल बेहतर करने के लिए कई कदम उठाये हैं। बनारस की 'गंगा–आरती' तर्ज पर यमुना आरती शुरू की गई है। सरकार यमुना के प्रदूषण पर 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था करने में जुटी है। कोशिश है कि अगले एक–दो सालो में औद्योगिक या घरेलू सीवेज का एक बूंद भी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में न जाने पाये। जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने संकल्प लिया है कि अगले 36 महीनों में यमुना को साफ कर दिया जाएगा।

बढ़ी जनशोधन क्षमता

दिल्ली में जनशोधन क्षमता बढ़कर 450 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) हो गई है, यानी 2250 मिलियन लीटर। एक मिलियन लीटर का मतलब 10 लाख लीटर होता है।

दिल्ली जल बोर्ड का लक्ष्य 2015 के अंत तक जलशोधन क्षमता को बढ़ाकर 500 एमजीडी करना है। दिल्ली में फिलहाल 17 स्थानों पर 30 जलशोधन संयत्र स्थापित हैं।

2016 में 'सिग्नेचर ब्रिज'

केजरीवाल सरकार साल 2016 में दिल्ली को सिग्नेचर ब्रिज का तोहफा देगी। कुतुब मीनार से भी ऊंचा यह ब्रिज दिल्ली की नई पहचान बनेगा। इस अद्भुत और अत्याधुनिक शिल्प परियोजना के पूरी होने का इंतजार पूरी दुनिया को है। यूँ तो यह बिल कई सालों से बन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद निर्माणकार्य ने काफी गति पकड़ी है। उम्मीद है कि मार्च 2016 तक इसका काम पूरा हो जाएगा।

भ्रष्टाचार पर वार...

जनलोकपाल बिल पास

दिल्ली विधानसभा ने शीतकालीन सत्र में जनलोकपाल बिल पास करके नया इतिहास रच दिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2013 में सरकार गठन के 49 दिन बाद इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। इस बार फिर विपक्ष ने प्रस्तावित जनलोकपाल बिल पर तमाम सवाल उठाये लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि वह हर हाल में इस विधेयक को पास करेगी और वैसा ही हुआ। 4 दिसंबर 2015 को जनलोकपाल बिल–2015 को दिल्ली विधानसभा से पारित कर दिया। इस बिल के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आएंगे और छह महीने में जांच पूरी करके छह महीने में ही ट्रायल भी पूरा होगा। लोकपाल के पास अपनी जांच एजेंसी होगी। आरोप सिद्ध होने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है और सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पांच गुना तक वसूला जा सकेगा।

जनलोकपाल बिल पास करने से पहले अन्ना हजारे की ओर से मिले सुझावों को शामिल करते हुए कुछ संशोधन भी किए गये। जनलोकपाल चुनने का काम एक सात सदस्यीय सेलेक्शन कमेटी करेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता के अलावा इन सबकी ओर से प्रस्तावित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूर्व जनलोकपाल और दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज भी शामिल होंगे। लोकपाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट से उन पर लगे आरोपों की जांच कराई जाएगी। इससे पहले विधानसभा दो तिहाई बहुमत से लोकपाल को हटाने का प्रस्ताव पारित करेगी।

दिल्ली जनलोकपाल बिल-2015

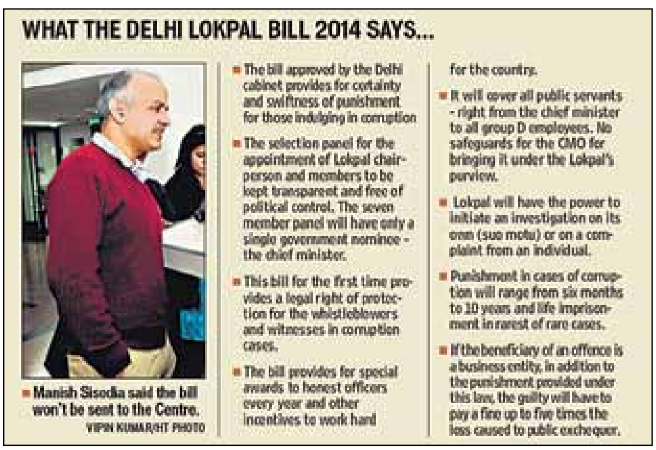

WHAT THE DELHI LOKPAL BILL 2014 SAYS...

- Manish Sisodia said the bill won't be sent to the Centre. VIPIN KUMAR/HT PHOTO

- The bill approved by the Delhi cabinet provides for certainty and swiftness of punishment for those indulging in corruption
- The selection panel for the appointment of Lokpal chairperson and members to be kept transparent and free of political control. The seven member panel will have only a single government nominee - the chief minister.
- This bill for the first time provides a legal right of protection for the whistleblowers and witnesses in corruption cases.
- The bill provides for special awards to honest officers every year and other incentives to work hard for the country.
- It will cover all public servants - right from the chief minister to all group D employees. No safeguards for the CMO for bringing it under the Lokpal's purview.
- Lokpal will have the power to initiate an investigation on its own (suo motu) or on a complaint from an individual.
- Punishment in cases of corruption will range from six months to 10 years and life imprisonment in rarest of rare cases.
- If the beneficiary of an offence is a business entity, in addition to the punishment provided under this law, the guilty will have to pay a fine up to five times the loss caused to public exchequer.

- ये बिल दिल्ली की सीमा में होने वाले किसी भी भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई के लिए है।
- आम जनता की शिकायत पर, स्वतः संज्ञान लेकर और सरकार की तरफ से शिकायत आने पर जांच हो सकेगी।
- लोकपाल का अपना एक इनवेस्टिगेशन विंग होगा।
- जांच के लिए अन्य विभागों और अधिकारियों की मदद ली जा सकेगी।
- जांच को अधिकतम 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। अति विशेष मामलों में ये समय–सीमा अधिकतम 12 महीने तक हो सकती है।
- लोकपाल का अपना प्रॉसिक्यूशन विंग होगा।
- समयबद्ध सीमा में जांच और समयबद्ध सीमा में मुकदमा लोकपाल की सबसे बड़ी ताकत है।
- करप्शन से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा।
- करप्शन में शामिल पब्लिक सर्वेंट को सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने का अधिकार होगा।
- इसके तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है। इसके अलावा 6 महीने से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ–साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।
- भ्रष्टाचार से सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पांच गुना तक जुर्माना लगेगा।
- ऊंचे पद पर बैठ लोग अगर करप्शन करते हुए पाए जाते हैं तो उनको कठोरतम सजा देने प्रावधान है।
- निजी कंपनियों के करप्शन के मामले में उनके पदाधिकारियों को दंडित करने का अधिकार है।
- भ्रष्टाचार उजागर करने वाले की सुरक्षा और उनको प्रशासनिक शोषण से बचाने का अधिकार लोकपाल के पास है।
- भ्रष्टाचार उजागर करने वाले की जान को अगर खतरा है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

एसीबी पर जंग जारी

दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) के जरिये दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने एसीबी की कमान खुद ले ली। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली सरकार के अधीन रहते जिस एसीबी ने 4 महीने में 52 केस दर्ज किये थे, वही सात महीने में सिर्फ दस केस दर्ज कर पाई।

पुल बनाने में सैकड़ों करोड़ बचाये

दिल्ली सरकार के लोकनिर्माण विभाग ने बचत की मिसाल कायम की है। आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल तक छह लेन के एलिवेटेड 247 करोड़ रुपये मंजूर किए गये थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट 145 करोड़ रुपये में ही पूरा हो गया।

इसी तरह मंगोलपुरी से मधुबन तक का एलिवेटेड कॉरीडोर के लिए 423.05 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था, लेकिन इसे सिर्फ 300 करोड़ रुपये में बना दिया गया।

मंत्री बरख़ास्त

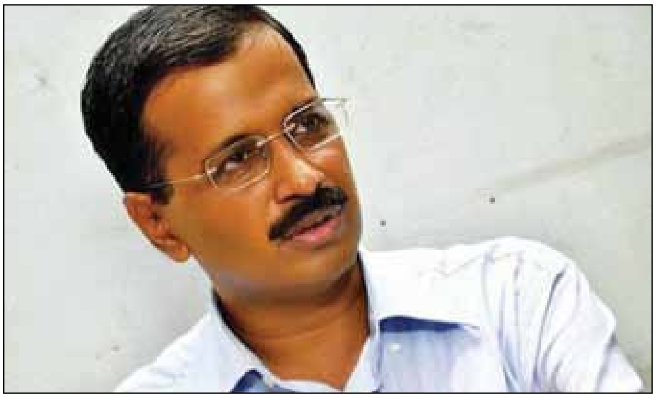

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ अपनी जंग में एक ऐसी रेखा खींच दी है जो केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के लिए चुनौती बन गई है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर अपने ही एक मंत्री को बरख़ास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मामले की सीबीआई जाँच की सिफारिश भी कर दी। बरख़ास्त किए गये मंत्री का नाम है आसिम अहमद खान। मटिया महल इलाके से विधायक आसिम अहमद खान के पास दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति के अलावा, पर्यावरण एंव वन, अल्पसंख्यक मामले और इलेक्शन विभाग भी था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बिल्डर से छह लाख रुपये रिश्वत मांगी। इस बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने बिना विलंब किए मंत्री को बरख़ास्त कर दिया गया। यही नहीं उन्होंने खुद प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को अपने इस कदम की जानकारी दी।

रसोई में रंग...

खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले लाभार्थियों की सौ फीसदी पहचान की गई। यह उपलब्धि 30 सितंबर 2015 तक हासिल कर ली गई।

ई-राशन कार्ड

ई–राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई। करीब 5.57 लाख राशनकार्ड धारकों ने ई–राशन कार्ड डाउनलोड किया। सुविधाओं की उपलब्धता और पारदर्शिता के लिहाज से यह व्यवस्था कारगर साबित हुई।

बायोमेट्रिक दुकानें

सरकारी उचित मूल्य की 40 दुकानों (एफपीएस) को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस के पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। इसके तहत बायोमेट्रिक प्रणाली से सत्यापान के बाद लाभार्थी को राशन इत्यादित मुहैया कराया जाता है। पारदर्शी वितरण व्यवस्था के लिहाज से इस बेहद महत्वपूर्ण प्रणाली से अगले छह महीने में दिल्ली की सभी 2400 उचित मूल्य दुकानों को इससे जोड़ दिया जाएगा।

कार्ड पोर्टेबिलिटी

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड
कार्ड नं. 077004559929
नाम: Birbati टाइप: PR एफ.एस.ओ.क्षेत्र: 46
पता: 330 HARIJAN MOHALLA new delhi, VILLLAGE GHITORNI, Delhi-110030
एफ.पी.एस.नाम: M/S BHARAT PROVISIONAL STORE(3347)
Approved by Mahish, FSO - 46 on 08/10/2014

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ। इसके तहत राशनकार्ड धारी उपभोक्ता अपने क्षेत्र में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सामान खरीद सकते हैं। इससे दुकानदारों में बेहतर सुविधा देने को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एफपीएस लाइसेंस के नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था जल्द शुरू होगी। इससे संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है।

कन्ज़्यूमर क्लब

उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सौ सरकारी स्कूलो में 'कन्ज़्यूमर क्लब' खोले जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा ताकि वे सेमिनार और अन्य गतिविधियों के जरिये उपभोक्ताओं को जागरूक कर सकें। भविष्य में दिल्ली के सभी स्कूलों में कन्ज़्यूमर क्लब खोले जाएंगे।

उपभोक्ता फ़ोरम

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम की एक और बेंच खोलने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही एक अन्य ज़िलास्तरीय उपभोक्ता फोरम भी शीघ्र कामकाज शुरू कर देगा।

ट्रकों में जीपीएस

एफसीआई के गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाने की योजना है ताकि उनकी सतत निगरानी हो सके। इससे दुकानों तक अनाज पहुँचने में विलंब नहीं होगा।

अक्सर जनता को दुकान पर राशन उपलब्ध न होने की बात सुननी पड़ती थी। दुकानदार यह नहीं बता पाता था कि राशन दुकान तक कब पहुँचेगा। जीपीएस सिस्टम लग जाने से यह समस्या दूर हो जाएगी।

जनता है मालिक...

एफ़ीडेविट समाप्त

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL C 410362

AFFIDAVIT
(Submitted by the Institution)

I, Dr. Balwant Singh s/o Late Sh. Moti Singh aged 58 years, resident of Uttarakhand (presently residing at Agastyamuni), in the capacity of Principal of the College/ Chairperson of College Level Executive Committee for Self Financed B.Ed. Programme of A.P.B. Government Postgraduate College Agastyamuni, District Rudrapayag of Uttarakhand, take oath on behalf of the Governing Body formed by the Government of Uttarakhand and state as under:-

1. That I am Chairperson of College Level Executive Committee/ Principal of A.P.B. Government Postgraduate College Agastyamuni, District Rudrapayag of Uttarakhand and signing this Affidavit on behalf of the Governing Body for which I am fully authorized.

2. That the Selection Committee/ Screening Committee for appointment of faculty has been constituted as per the policy of State Government and the following were the Members of the Committee :

Name	Status in Selection Committee
Dr. Balwant Singh, M.Sc., Ph.D.	Principal/ Chairperson
Dr. Pratap Singh Jangwan, M.Sc., Ph.D.	Senior Teacher/ Member
Dr. Pushpanjali Arya, M.A., Ph.D.	SC representative/ Member
Dr. Lalit Mohan Pande, M.A, M.Ed, Ph.D.	Subject Expert/ Director's Nominee

दिल्ली सरकार ने 200 तरह के एफ़ीडेविट खत्म करने का फैसला किया। अब लोगों को अलग–अलग विभागों या दूसरे संस्थानों में अपनी योग्यता के प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए हलफनामे देने की जरूरत नहीं रह जाएगी। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वयंसत्यापन को ही पर्याप्त माना जाएगा। गौरतलब है कि लोगों को अपने ही प्रमाणपत्रों को सही ठहराने के लिए हलफनामे बनवाने के लिए काफी परेशान होना पड़ता था। आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली के आम नागरिक पर अपना विश्वास जताया है।

सिटीज़न चार्टर

दिल्ली की जनता को अब किसी दफ़्तर में अपने काम के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) संशोधन विधेयक, 2015 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस कानून के बन जाने से जनता को तय वक्त पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यानी निश्चित अवधि में सेवाएँ प्राप्त लोगों का कानूनी अधिकार होगा।

1984 के दंगा पीडितों को बढ़ा मुआवज़ा

दिल्ली में पहली बार सरकार गठन के साथ ही केजरीवाल सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में जुट गई थी। सरकार ने दंगों की जाँच के लिए विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में हुए जुल्म का हिसाब हर हाल में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 नवंबर 2015 को, पाँच लाख रुपये प्रति परिवार के हिसाब से बढ़े हुए मुआवज़े का चेक बाँटा। दिल्ली सरकार इस मद में 130 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस राहत राशि से 2600 परिवारों को फायदा होगा।

महिला सुरक्षा आयोग का गठन

दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिला सुरक्षा आयोग का गठन किया है। दिल्ली विधानसभा ने इस आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। आयोग का चेयरमैन अवकाश प्राप्त जिला जज दिनेश दयाल को बनाया गया है। इसके अलावा दो महिला समाज सेवियों को इसका सदस्य बनाया गया है। आयोग का कार्यकाल दो साल का होगा और वह हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। आयोग फरवरी 2013 के बाद हुए महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और यौन उत्पीड़न तथा हिंसा के मामलों को देखेगा।

ड्यूटी पर मृत्यु हुई तो एक करोड़

दिल्ली सरकार युद्ध, किसी आपदा या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान मारे जाने वाले सैनिकों, अर्धसैनिकों, पुलिसकर्मियों, सिविल डिफेंस कर्मियों और होमगार्डों के परिजनों को एक करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान देगा। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि रक्षाकर्मी, जिनका नौकरी के समय दिल्ली का पता है, और वे युद्ध या फिर किसी आपरेशन के दौरान मारे जाते हैं, उनके परिजनों को सरकार एक करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान देगी। इसी तरह का अनुदान अर्धसैनिकों के परिजनों को भी मिलेगा। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे जाते हैं तो इसी तरह का अनुदान उनके परिवारों को भी मिलेगा। होमगार्डस और सिविल डिफेंसकर्मी यदि दिल्ली सरकार के किसी विभाग के अधीन ड्यूटी करते हुए मारे जाते हैं तो सरकार उनके परिजनों को भी आर्थिक अनुदान देगी।

सीसीटीवी

दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के वादे को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि सीसीटीवी का असर किसी की निजी जिंदगी में नहीं पड़ेगा। पहले चरण में 4 लाख सीसीटीवी लगाये जाएंगे। सरकार खासतौर पर ऐसे डार्क स्पाट्स को चिन्हित करके सीसीटीवी लगाएगी जहाँ अपराध होने की आशंका ज्यादा होती है।

जॉब समिट

दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जॉब समिट आयोजित करा रही है। इससे हजारों नौजवानों को फायदा हुआ है। दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट के साथ कई नामी कंपनियाँ भी जुड़ी हैं। जॉब समिट का आयोजन रोजगार विभाग के चार ऑफिस किर्बी प्लेस, आर.के.पुरम, विश्वास नगर (शाहदरा) और पूसा रोड में किया जाता है।

किसानों को सर्वाधिक मुआवज़ा

केजरीवाल सरकार ने किसानों के हित में ऐसे कदम उठाये जो मिसाल बन गये हैं। फसल बर्बाद होने पर देश मे सबसे ज्यादा मुआवज़ा दिल्ली के किसानों को दिया जा रहा है। सरकार बनने के दो महीने के अंदर ही, अप्रैल 2015 में किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवज़ा देने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली सरकार के इस कदम का असर दूसरे प्रदेशों पर भी पड़ा जहाँ के किसानों ने मुआवज़ा बढ़ाने की माँग की।

शहर होते गाँव

अक्टूबर 2015 में दिल्ली सरकार ने 95 गाँवों में ग्राम सभा की हजारों एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के हवाले कर दिया। अब यह गाँव शहरी इलाके में आ गये हैं और यहां की जमीन डीडीए की लैंड पूलिंग पालिसी के तहत आ जाएगी। भविष्य में इन गाँवों के विकास को काफी गति

मिलेगी। केजरीवाल सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून को किसान विरोधी बताते हुए लगातार इसे किसानों के हित में बदलने की माँग उठाई।

बजट में जनता की राय

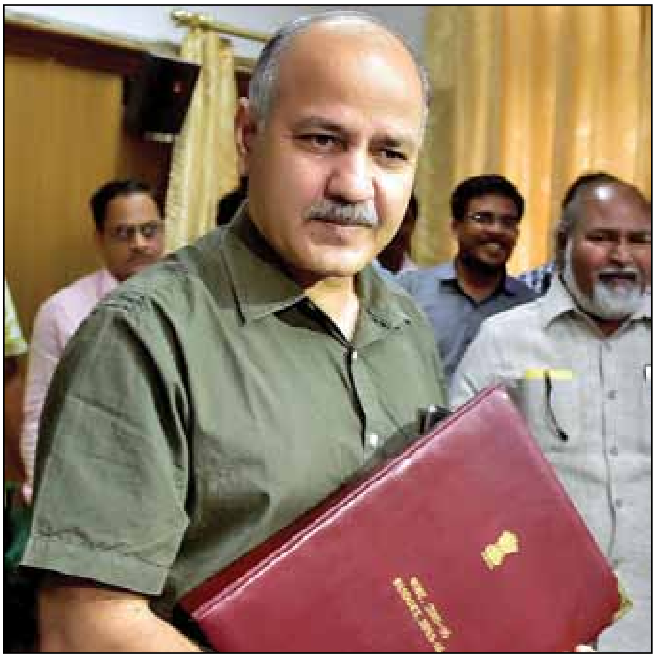

अपनी तरह का पहला प्रयोग करते हुए दिल्ली सरकार ने जनता की राय लेकर बजट बनाया। पिछली बार 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला सभा हुई थी और जनता की राय ली गई थी। एक साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने सभी 70 विधानसभाओं में मोहल्ला सभाएँ कराने का एलान किया। मोहल्ला सभाओं में लोगों की राय से योजनाएँ बनती हैं। इसके लिए सुझावों पर वोटिंग के जरिये प्राथमिकताएँ तय होती हैं। यह लोग ही तय करेंगे कि उनके इलाके में कौन सा काम सबसे जरूरी है जिसे सबसे पहले कराया जाना चाहिए। मोहल्ला सभाओं के प्रयोग ने दिल्ली की जनता में प्रशासन के भागीदार होने का अहसास भरा है।

दिल्ली के लोग हर साल 1 लाख 67 हजार करोड़ रुपये केन्द्र को टैक्स के रूप में देते हैं। स्टेट शेयर के नाम पर वापस मिलते हैं सिर्फ 325 करोड़ रुपये।

कार्यक्रम आयोजन को सिंगल विंडो सिस्टम

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को ऐसी राजधानी में तब्दील कर दिया जहाँ सांस्कृतिक या अन्य आयोजन बेहद आसानी से किये जा सकते हैं। पहले दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कई दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सरकार ने 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' शुरू कर दिया है। आयोजन की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पहली अनुमति मिली विश्वप्रसिद्ध संगीत कंडक्टर जुबिन मेहता के शो को। जुबिन मेहता ने खचाखच भरे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आस्ट्रेलियाई ऑर्केस्ट्रा के साथ यादगार प्रस्तुति दी जिसकी दिल्ली की जनता ने भरपूर सराहना की। महान संगीतकार ए.आर. रहमान का सात साल बाद दिल्ली में शो आयोजित हुआ।

बिल बनवाओ-इनाम पाओ

दिल्ली सरकार ने 'बिल बनवाओ– इनाम पाओ' नाम से नई योजना शुरू की है। योजना के तहत लोगों से अपील

की गई है कि जो भी सामान खरीदें, उसकी पक्का बिल जरूर लें। सरकार ने इस बाबत 50 हजार रुपए तक का इनाम रखा है। इसके लिए खरीदी गई वस्तु की कीमत 100 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बिल की कॉपी को विभाग की वेबसाइट पर सात दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। प्रत्येक बिल के लिए एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है और एसएमएस के जरिए ग्राहक को भेज दिया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत हर महीने इनाम दे रही है। इससे उपभोक्ता पक्की रसीद देने का दबाव दुकानदारों पर बना रहे हैं जिससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिल रहा है।

व्यापारियों पर रेड बंद

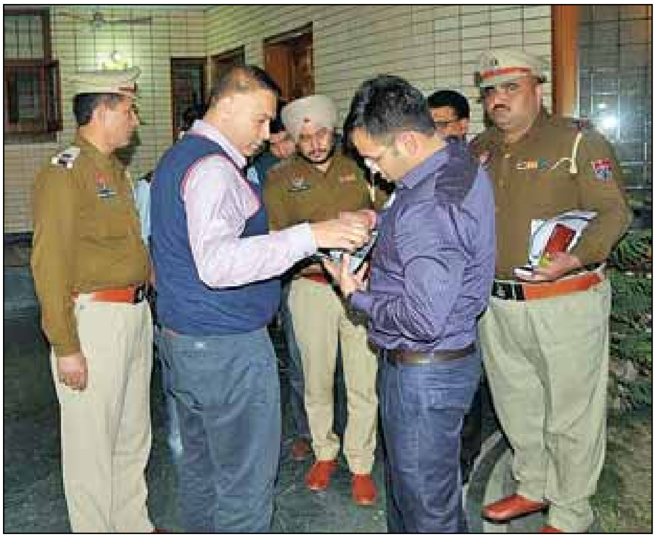

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने व्यापारियों पर आये दिन पड़ने वाले छापों की परंपरा खत्म कर दी है। सरकार ने रेड–राज खत्म करते हुए घोषणा की कि वह व्यापारियों पर पूरी तरह विश्वास करती है। अब व्यापारी अपने टैक्स का आकलन खुद करते हैं और रिटर्न को आनलाइन भरा जाता है। जिसे सरकार पूरी तरह स्वीकार करती है। साथ ही उनकी शिकायतों के निपटान के लिए पारदर्शी व्यवस्था कायम की गई। वैट के लिहाज से दिल्ली में 105 वार्ड और 10 जोन हैं। दो जोन ऐसे भी हैं जो खास एक करोड़ से अधिक सालाना रिटर्न देते हैं। दिल्ली में करीब तीन लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं। जिन भी व्यापारियों का सालाना टर्नओवर है, उनका वैट विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

ई-कामर्स का नियमन

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के दुकानदारों को भरोसा दिलाया है कि ई–कामर्स (ऑनलाइन खरीददारी) के बढ़ते चलन के बीच उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि ई–कामर्स कंपनियों को मनमानी करने की छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के लिए हर तिमाही वैट रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद उनकी सप्लाई चेन और आउटसोर्सिंग पर नजर रखना है।

वैट विभाग ने एक नई पहल करते हुए अपने 10 जोन को एक साथ करते हुए नया ई–कामर्स जोन गठित किया है। सभी पंजीकृत ई कामर्स कंपनियों को इसी जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली की हर कूरियर कंपनी को 10 हजार से ज्यादा मूल्य के सामान की डिलिवरी करने पर वैट विभाग में रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। ■

मौजूदा वित्तीय वर्ष में 11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज कराते हुए दिल्ली में 20 हजार करोड़ से ज्यादा का वैट कलेक्शन हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष में महज 2 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

दिल्ली में लोक-उत्सव की धूम

दिल्ली में इस बार बसंत का स्वागत लोक–उत्सव के निराले अंदाज में हुआ। दिल्ली की हिन्दी अकादमी ने दिल्ली के अलग–अलग इलाकों में 21 से 24 फरवरी के बीच चार दिवसीय आयोजन के जरिये पूरे देश का रंग राजधानी में उतार दिया। कलाकारों के जरिये पूरा देश दिल्ली में धड़कता नजर आया।

पहला आयोजन गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के महावीर स्वामी पार्क में रविवार, 21 फरवरी 2016 को किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति का रंग बिखेरा। कार्यक्रम का उद्‌घाटन हिंदी अकादमी उपाध्यक्ष मैत्रेयी पुष्पा, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार वाजपेयी, हिन्दी अकादमी के सचिव श्री जीतराम भट्ट ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

दूसरा आयोजन 22 फरवरी, 2016 को दिल्ली हाट, जनकपुरी में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात की सांस्कृतिक झलक पेश की गयी। तीसरा आयोजन 23 फरवरी, 2016 को दिल्ली हाट, पीतमपुरा में किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड से आये लोक कलाकारों के दल ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वहाँ की लोककला, संस्कृति और भाषा को दिल्ली में जीवंतता प्रदान की।

अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे चार दिवसीय लोक उत्सव की कड़ी का चौथा और आखिरी आयोजन 24 फरवरी, 2016 को दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में किया गया। इसमें बुंदेलखण्ड और मध्य प्रदेश से आये लोक कलाकारों के दलों ने अपनी सुंदर सांस्कृतिक लोक प्रस्तुतियों के माध्यम से न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि अपनी संस्कृति, भाषा, लोक की अमिट छाप भी छोड़ी।

कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए अकादमी के सचिव ने कहा कि लोक संस्कृति, कला, साहित्य, संस्कृति और भाषा में हमारे विविधरंगी देश के अलग–अलग रंग नजर आते हैं। चूँकि दिल्ली में तमाम प्रांतों के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति, भाषा और कलाबोध भिन्न–भिन्न हैं, तो हिंदी अकादमी का प्रयास है कि उनके लिए ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिससे वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

कार्यक्रम में अकादमी की उपाध्यक्ष और चर्चित साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा, अकादमी की संचालन तथा कार्यकारिणी समिति के माननीय सदस्य विकास नारायण राय के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ■

'रोहित एक्ट' बनाए केंद्र सरकार-अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से तुरंत रोहित एक्ट बनाने की माँग की है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के तेजस्वी शोधछात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद पूरे देश में आंदोलन जैसा माहौल है और रोहित एक्ट बनाने की माँग तेज होती जा रही है। यानी एक ऐसा कानून बने जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े तबकों के प्रति भेदभाव के खिलाफ दंड का प्रावधान हो। चूँकि रोहित वेमुला इस भेदभाव और उत्पीड़न का राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है, इसलिए कानून उसके नाम पर बने।

23 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर–मंतर पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए 'रोहित एक्ट' बनाये जाने की पुरजोर वकालत की। इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर से छात्र–युवा दिल्ली पहुँचे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोहित वेमुला के साथ हुई नाइंसाफी को याद करते हुए कहा कि रोहित ने जो चिट्ठिया लिखीं उसमे उसके गरीब और दलित होने की वजह से हो रहे उत्पीड़न की चीख सुनाई देती है। रोहित बार–बार कह रहा था कि उसे सस्पेंड न किया जाये, वरना उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। उसकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। हास्टल से निकाल बाहर किया गया। केजरीवाल ने कहा कि रोहित बहुत होनहार लड़का था। बेहद गरीब और दलित परिवार से आने के बावजूद उसने पढ़ाई में जैसी उपलब्धियाँ हासिल कीं, उस पर तो देश और समाज को नाज करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था संभाल रहे मंत्रिओं ने उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैसा इंसाफ है कि केस दर्ज होने के बावजूद आरोपी मंत्रियों से पूछताछ तक नहीं हुई जबकि पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने दलितों और गरीबों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इससे पहले आईआईटी मद्रास में अंबेडकर–पेरियार स्टडी सर्किल पर रोक लगाई गई। मध्यप्रदेश में एक दलित शिक्षक पर हमला बोला। मोदी सरकार को अंदाजा नहीं है कि जिस तरह से छात्र–युवा उसके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बाँटा जा रहा है। बलात्कारी और हत्यारे भी कह रहे हैं कि उन्होंने देश विरोधी होने की सजा दी है। ऐसे लोगों की नजर में सबसे बड़ा देशभक्त है नाथूराम गोडसे और सबसे बड़े देशद्रोही हैं महात्मा गाँधी। इन दिनों सारे लुच्चे–लफंगे देशभक्त बनकर घूम रहे हैं जबकि जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया जैसे नौजवानों को बगैर किसी सबूत के जेल में डाला गया है।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ, ਬੇਮਿਸਾਲ !

14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ (70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤ ਕੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਹਿਲੋਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ– 'ਕੇ ਜਰੀਵਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ।'

ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਬੇਮਿਸਾਲ !

14 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ-

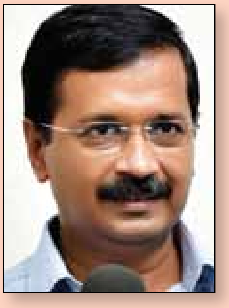

ਸਵਾਲ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਸੀਐਮ) : ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਉ, ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

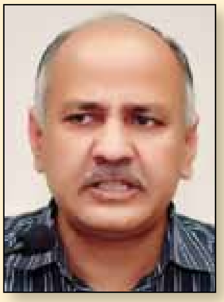

ਸਵਾਲ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ (ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ) : ਇਸ ਸਾਲ 25 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 8,000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

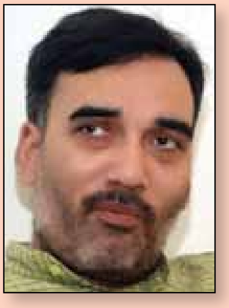

ਸਵਾਲ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ ?

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ (ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ) : ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।

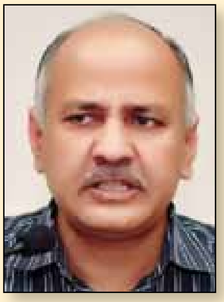

ਸਵਾਲ : ਦਿੱਲੀ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਡੀਐਸਐਸਐਸਬੀ) ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਹੋਏ ਟੀਜੀਟੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ?

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ (ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ): ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਈ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇ ਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

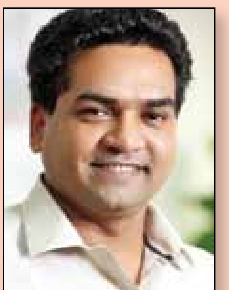

ਸਵਾਲ : ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ) ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਆਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਿਜਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ : ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ): ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲੈਬ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪਧਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਲਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

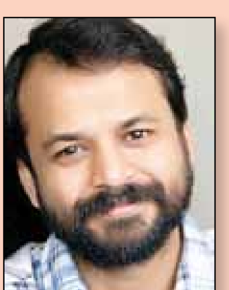

ਸਵਾਲ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ?

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਡਾਯਲਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ): ਦਿੱਲੀ ਡਾਯਲਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤਕ 70 ਤੋਂ 80 ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਂਟੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਲ...

ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 400 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ।

ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬੇਹਦ ਘਟ

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕੇਵਲ 0.14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘਟ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਲੋਡਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਕ ਵਕਤ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

ਸੇਟੇਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ

ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੇਟੇਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 30 ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 55000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ

ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 93 ਰੁਪੈ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਲਖ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਬ ਬਦਲ ਕੇ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50-60 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਊਥ ਐਮਸੀਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 1.25 ਲਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ

ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਣ ਜਾਂ ਗੁਣਵਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਨਏਬੀਐਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਝਣ ਲਗੀ ਪਿਆਸ...

ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ (ਕਰੀਬ 700 ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੁਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 8.99 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਬੇਮਿਸਾਲ !

ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਮਾਫ

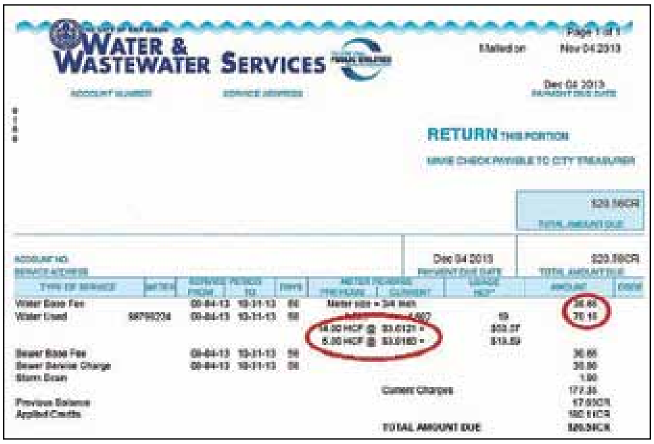

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰੇਗੰਢ 'ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ

ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ 440 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 1.2 ਲਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ 494 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੀਟਰ

ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਚੀਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪੈ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3310 ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਉਪਯੋਗ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ

2011 ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਐਮਜੀਡੀ (ਮਿਲਿਅਨ ਗੈਲਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਵਾਰਕਾ ਉਪਨਗਰ, ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ, ਦੌਲਤਪੁਰ, ਓਜਵਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 13 ਲਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 2002 ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਵਾਨਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

20 ਐਮਜੀਡੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਵਾਨਾ, ਨਰੇਲਾ, ਸਨੌਠ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਖਲਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 7 ਐਮਜੀਡੀ ਤੋਂ 20 ਐਮਜੀਡੀ ਹੋਈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ

ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 136 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ 148 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 78 ਵਾਧੂ ਟੈਂਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜਸਵ ਵਧਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 19.58 ਲਖ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸਵ ਮਿਲਿਆ।

ਸੁਧਰਦੀ ਸਿਹਤ...

ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ

1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ

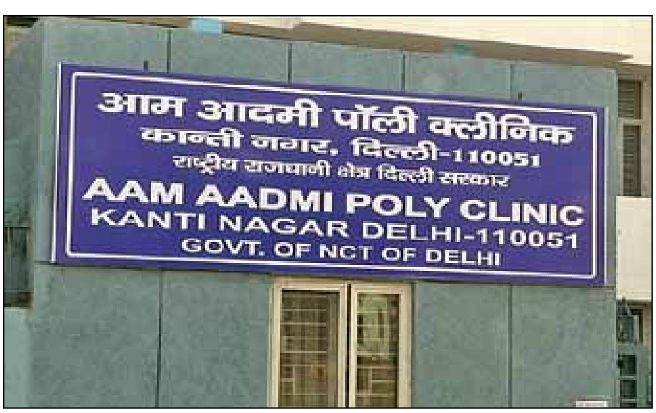

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 22 ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1200 ਮਰੀਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸੇ 150 ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ

ਪੀਰਾਂਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਸੌ ਮਰੀਜ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ 20 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1000 ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧਣਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਡ

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 20000 ਬੈਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ 10000 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 70 ਫੀਜਿਯੋਥੇਰੇਪੀ ਅਤੇ 250 ਡੇਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂਰਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦਿਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਦੀਪੁਰ, ਨਾਂਗਲੋਈ, ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ, ਸਿਰਸਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਾ ਲਗਣ।

ਸਿਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ...

21 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਰੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 21 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 63 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ 25 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਮੀਨ ਦੇ 38 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8,000 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਲੈਬ, ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਹਾਲ ਆਦਿ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 40 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 40.1 ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਟੇਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੇਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2012-13, 2013-14, ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 120 ਦਿਨ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇੰਨੇ ਘਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 10,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਡਸਿਲ) ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਾਯਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਲੈਬ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਸਕੂਲੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 4 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ

ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ

ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਿਟ੍ਰਯਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੁਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰਯਲ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮਿਨਿਸਿਟ੍ਰਯਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

10 ਲਖ ਤਕ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਲੋਨ

ਹਾਯਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਕਿਲ ਸੈਂਟਰਸ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਆਈਟੀਆਈ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਹੋਸਟਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰਖਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਮਾਰਜਿਨ, ਮਨੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਮਸੀ) ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਰੇਂਟਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 1011 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਸਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਐਸਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡ ਤੋਂ ਮੀਲ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਤਕ ਵਿਚ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 9ਵੀਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਅਨਰਿਚਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 54 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਯਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦਸ ਤਕ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕੇ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਏ।

ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ'' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ...

ਆਡ-ਈਵਨ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਜਿਹਾ ਅਭਿਨਵ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ। ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਲਖ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਟ ਉਤਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਾ 66/192 ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਆਟੋ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨਸੀਆਰ (ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 15000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 30000 ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

پہلا سال، بے مثال!

بہتر بسیں

دہلی کی بسوں میں عورتوں کی حفاظت کے لئے 3200 مارشل تعینات کئے جا چکے ہیں۔ اگلے چھ سے 9 مہینے میں ڈی ٹی سی 1000 اے سی بسیں اتارے گی۔ اس کے علاوہ کلسٹر درجے میں بھی ایک ہزار بسیں چلائی جائیں گی۔ دہلی کے سبھی بسوں میں آئندہ چھ مہینے میں سی سی ٹی وی / جی پی ایس / وائی فائی سہولت ہوگی۔ اس کے لئے ساری تیاری کر لی گئی ہے۔ ٹنڈر جلد جاری ہوں گے۔

نئی سڑک

دہلی کی سڑکوں کو سنوارنے کے لئے سرکار نے بڑی پہل کی ہے۔ سرکار نے 1200 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑکوں کو ری-ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکار اس پر قریب پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ کریگی۔ سرکار کا زور ایسے سڑک بنانے کا ہے جن پر گاڑی والوں کے ساتھ ساتھ پیدل اور سائیکل والوں کیلئے محفوظ ہوں۔ ساتھ ہی جسمانی طور سے معذور لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔

اس پروجکٹ کے تحت گلاس لفٹ، ٹوائیلیٹ بلاک، سولر اسٹریٹ لائٹ، رین واٹر ہارویسٹنگ کے سسٹم بھی لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریہڑی پٹری والوں کے لئے بھی جگہ ہوگی۔ فی الحال 10 سڑکوں کو پائلٹ پروجکٹ کے تحت چنا گیا ہے۔ جہاں جلد ہی ری ڈیزائن کا کام شروع ہوجائیگا۔

دو منزلہ پل

دہلی سرکار نے عوامی ٹرانسپورٹ کی حالت سدھارنے کے لئے ایک دور اندیش منصوبہ بنائی ہے۔ اس پروجکٹ کے تحت دو منزلہ ایلی ویٹیڈ روڈ بنیں گے۔ ایک روڈ پر صرف بسیں چلیں گی اور دوسری پر کار۔ اوپری منزل پر بسیں چلیں گی۔ بنا کسی رکاوٹ کے ان کا سفر تیزی سے پورا ہوگا جس سے میٹرو کی طرح ان کا بھی ٹائم ٹیبل بن پائے گا۔ ان بسوں کی آسان اور آرام دہ سفر لوگوں کو پرُکشش کریگی کہ وہ نجی ٹرانسپورٹ کا استعمال نہ کریں۔

راہیں نئی نئی ...

طاق وجفت

دہلی سرکار نے طاق وجفت جیسا نیا تجربہ کر کے ایک تاریخی شروعات کی۔ ملک میں پہلی بار ایسی شروعات ہوئی جس کے دل موہ لینے والے نتیجے آئے۔ 1 جنوری 2016 سے 15 جنوری کے بیچ اس تجربہ کی عوام نے بھرپور تعریف کی اور اس کا ساتھ دیا۔ ہر دن قریب 10 لاکھ گاڑیاں سڑکوں پر کم اتری۔ جس سے آلودگی میں کمی آئی ساتھ ہی جام کی مشکل سے نجات ملی۔ عوام نے اس اسکیم کو پھر سے شروع کرنے کے معاملہ میں رائے دی ہے۔ جس پر سرکار عمل کرنے جا رہی ہے۔

کار فری ڈے

لوگوں کو آلودگی کی مسئلہ کے تئیں بیدار کرنے کیلئے ہر مہینے کی 22 تاریخ کو کار فری ڈے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو عوامی ٹرانسپورٹ انتظام کے استعمال کیلئے آمادہ کرنا بھی ہے۔

آٹو چلانے والوں کو راحت

آٹو رکشہ اور ان کے چالکوں سے جڑے تمام مسائل دور کی گئی۔ دفعہ 66/192 میں ترمیم کر کے پولیس سے آٹو ضبط کرنے کا حق لے لیا گیا۔ اب کام ختم کر کے گھر جا رہے آٹو ڈرائیوروں کا بھی چالان نہیں کیا جا سکتا۔ این سی آر (ہریانہ، یوپی) کے لئے چار ہزار سے زیادہ آٹو پرمٹ جاری کئے گئے۔

ای رکشا

ای رکشا کے رجسٹریشن کی تکنیک طے ہوئی۔ ای رکشا پر سرکار 15000 ہزار روپے کی سبسڈی دیتی ہے۔ جس سے جلد ہی 30000 روپے کر دیا جائے گا۔ قریب 4600 ای رکشا رجسٹریشن ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ''پوچھو'' ایپ پھر سے لانچ کیا گیا۔ اس سے عوام کو آٹو اور ٹیکسی سہولت پانا آسان ہوا۔ ساتھ ہی آٹو چلانے والوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔

پہلا سال، بے مثال!

ایجوکیشن محکمہ نے ان چناؤ کے لئے ہر اسکول میں باقاعدہ آبزرور تعینات کئے۔ اس سے سرپرستوں کی بھاگیداری اسکول میں بڑھی ہے۔ وہ صاف صفائی سے لے کر مڈے میل کی کوالٹی تک میں وقت وقت پر نظر رکھتے ہیں۔ ملک میں یہ اپنی طرح کی پہلی کوشش ہے۔

خوبیوں کے ساتھ پڑھائی

یہ بہت صاف ہے کہ پہلے کچھ سالوں میں ایجوکیشن کی خوبیاں گری ہیں۔ بچوں کو سال در سال پاس کر دیا جاتا ہے۔ بھلے ہی وہ ٹھیک سے سیکھ پائے ہوں یا 9 ویں میں بچے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو بنیادی جانکاری بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے دہلی کے سبھی سرکاری اسکولوں میں ڈیڑھ مہینے کا خاص لرننگ انسچپمنٹ پروگرام چلایا گیا۔ اس کا بہت دلچسپ اثر دکھا ہے۔ اب باقی صوبوں کے لوگ اس پروگرام کو سمجھنا چاہتے ہیں تا کہ وہ اپنے یہاں بھی اسے لاگو کر سکیں۔

بدلاؤ کے تجربہ

دہلی کے ایجوکیشن حالت کو بہتر بنانے کیلئے 54 اسکولوں میں پائلٹ پروجکٹ چلائے جا رہے ہیں۔ نوٹ ڈیٹینشن پالیسی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تا کہ کلاس دس تک بن پڑھے بھی پہنچ جانے کا سلسلہ تھمے۔ نجی اسکولوں کے منیجمنٹ کی منمانی روکنے کے تمام قدم اٹھائے گئے ہیں۔ پھر چاہے معاملہ منیجمنٹ کوٹے کا ہو یا منمانی فیس کا۔ سرکار عدالتوں میں بھی اس مسئلے پر مضبوطی سے عوام کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔

کھیل یو نیور سٹی

سرکار نے دہلی میں نئی کھیل سنسکرت یافتہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ وارڈ درجہ سے لڑکے لڑکیوں میں کھیلوں کیلئے دلچسپی پیدا کی جائے تا کہ ذہینوں کو وقت رہتے پہچان لیا جائے اور انہیں ضروری سہولتیں دے کر تراشا جائے۔ یہی نہیں آگے چل کر ذہین وقابل طلباء کو کھیلوں میں ہی ڈگری حاصل ہو جائے تا کہ ان کے کیریئر کی راہ میں اڑچن نہ آئے۔ سرکار نے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے دہلی میں ''اسپورٹس یونیورسٹی'' قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔

پہلا سال، بے مثال!

اسکولوں میں صدر مدرس کی مدد کیلئے اسٹیٹ منیجر کا انتظام ہوا اور اسکی تقرری بھی خود صدر مدرس ہی کرے۔ اسٹیٹ منیجر ایک موبائل ایپ کے ذریعہ روزانہ اپنے اپنے اسکول کی بنیادی سہولتوں کی ذریعہ سے ایجوکیشن محکمہ کے اعلیٰ افسران سمیت نائب وزیر اعلیٰ کو بھی آگاہ کرا رہے ہیں۔

پرنسپل کو حق

اسکولوں میں منسٹریل اسٹاف کی بھاری کمی کو دیکھتے ہوئے پرنسپل خود ریٹائرڈ ملازمین کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر منسٹریل کام کیلئے مقرر کرسکیں گے۔ اس سے اساتذہ کے اوپر منسٹریل کام کرنے کا اضافی بوجھ کم ہوجائے گا۔

10 لاکھ تک کا ایجوکیشن لون

ہائر ٹیکنیکل اور سِکل ایجوکیشن کیلئے اب دہلی سرکار 10 لاکھ روپے تک کا لون اپنی گارنٹی پر دلا رہی ہے۔ دہلی کے سبھی یونیورسٹیوں، کالجوں، تکنیکی تنظیموں، سِکل سینٹر، پولی ٹکنیک، آئی ٹی آئی وغیرہ میں پڑھائی کیلئے لون ملتا ہے۔ اس یوجنا میں کالج فیس، ہاسٹل خرچ کے ساتھ ساتھ کتابوں، کمپیوٹر وغیرہ کے لئے بھی لون ملتا ہے۔ پہلے اسٹوڈینٹس کو ایجوکیشن لون کے لئے قیمتی چیز گروی رکھنے یا دوسری گارنٹی کی ضرورت ہوتی تھی۔ لون کیلئے والدین کی پراپرٹی یا مالی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ 10 لاکھ روپے تک کے لون کی گارنٹی سرکار خود لے رہی ہے ساتھ ہی پروسیسنگ چارج مارجن منی، تھرڈ پارٹی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے۔

والدین کی بھاگیداری

سرپرست کی بھاگیداری نے بدلی اسکولوں کی حالت، اسکول منیجمنٹ کمیٹی (ایس ایم سی) کے ذریعہ سرپرست کی بھاگیداری بڑھانے سے پوری اسکولی انتظام میں کئی اچھے بدلاؤ آئے ہیں۔ دہلی سرکار کے سبھی 1011 اسکولوں میں ایس ایم سی ممبر کا جمہوری طریقے سے چناؤ ہوا جو تاریخی تھا۔ سرپرستوں کی باقاعدہ ووٹر لسٹ تیار کی گئی۔ لاکھوں سرپرستوں نے ایس ایم سی ممبران کے چناؤ کے لئے ووٹنگ کی۔ چناؤ کے لئے باقاعدہ پرچہ نامزدگی فارم بھرے گئے۔ اس چناؤ میں حصہ لینے والے ہر شخص کو اپنے پرچہ نامزدگی فارم کے ساتھ 10 سرپرستوں کے دستخط کرانا بھی لازم کیا گیا تھا۔

آن لائن امتحان

دہلی میں ایسا پہلی بار ہوگا جب اتنے کم وقت میں 10000 ٹیچروں کی بھرتی عمل پوری کرلی جائیگی۔ بھارت سرکار کی مینی رتن انٹر پرائزٹ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ انڈیا لمیٹیڈ (ایڈسِل) یہ آن لائن امتحان لیگی۔

اسکولوں میں سی سی ٹی وی

سبھی سرکاری اسکولوں کے سبھی کمروں، گلیاروں وغیرہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی شروعات ہوچکی ہے۔ پائلٹ پروجکٹ کے طور پر دو اسکولوں کے سبھی کمروں، لیب، گلیاروں وغیرہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے۔ نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے جا کر ان کا معائنہ کیا۔ اس دوران بچوں نے بتایا کہ اب انکے سامان چوری نہیں ہوتے۔ وہ کلاس میں زیادہ دھیان دے پاتے ہیں۔ ٹیچر پہلے کے مقابلے میں زیادہ ریگولر ہوگئے ہیں۔ ہر کلاس کے بچوں اور ٹیچروں نے کہا کہ سی سی ٹی وی لگنا چاہیئے۔

اسکولوں میں صاف صفائی

صاف صفائی کے معاملے میں سرکاری اسکولوں کی حالت بہت خراب تھی۔ کئی بڑے اسکولوں میں بھی صرف ایک یا دو صفائی ملازمین ہوتے تھے جس سے پوری انتظام بدتر حالت میں پہنچ گئی تھی۔ اسے درست کرنے کے لئے سرکار نے کئی بڑے اہم قدم اٹھائے۔ اسکولوں صفائی انتظام کو درست کرنے کے لئے سرکار نے نئے ٹنڈر سے اب ہر اسکولوں کو کم سے کم 4 صفائی ملازمین مل جائیں گے۔ ایپ کے ذریعے صاف صفائی کی حالت پر سرکار کی آن لائن نظر رہتی ہے۔

اسٹیٹ منیجر

ہر اسکول میں ہر پالی میں صدر مدرس اور ٹیچروں کی مدد کے لئے ایک اسٹیٹ منیجر کی تقرری کی جا رہی ہے۔ یہ شاید ملک میں پہلی بار کیا گیا ہے کہ

پہلا سال، بے مثال!

نئے اسپتال

سرکار نے پانچ نئے اسپتالوں کے لئے مادی پور، ناگلوئی، سریتا وہار سرس پور اور وکاس پور میں جگہ فائنل کردی ہے۔ اس کے لئے 10 اور اسپتالوں کے لئے ڈی ڈی اے جگہ مانگی گئی ہے۔ پرانے اسپتالوں کی حالت کو اس طرح سے درست کیا جارہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح پرائیویٹ اسپتالوں سے کم نہ لگیں۔

تعلیمی کرانتی...

21 نئے اسکول، 200 اسکولوں کے برابر کمرے

دہلی میں 21 نئے اسکول بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ جہاں جولائی 2016 سے پڑھائی شروع ہوگی۔ 63 نئے اسکولوں پر کام جاری ہے۔ پی ڈبلو ڈی 25 اور نئے اسکول بنا رہے ہیں۔ گرام سبھا زمین کے 38 پلاٹ پر نئے اسکول کھولنے کی عمل شروع کردی گئی ہے۔

اس کے علاوہ موجودہ اسکولوں میں 8000 نئے کمرے جوڑے جارہے ہیں۔ ان میں کلاس روم، لیب، کثیر المقاصد ہال وغیرہ ہیں۔ اوسطاً ایک اسکول میں 40 کمرے ہوتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 200 نئے اسکولوں کے برابر کا انفرا اسٹکچر پہلے سال ہی تیار ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ پانچ دیگر اسکولوں میں ڈبل شفٹ کی اجازت دے دی گئی ہے۔

10 ہزار عارضی ٹیچر

دہلی کے اسکولوں میں پڑھائی کی خوبیاں بہتر بنانے کے لئے 10000 نئے عارضی ٹیچروں کی تقرری کی عمل شروع ہوگئی ہے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے طریقہ کاروں کے مطابق ٹیچرس۔طالب علم تناسب کو 40:1 تک لانے والا دہلی ملک کا پہلا راجیہ بن جائے گا۔ اس متعلقہ میں گیسٹ ٹیچروں کیا گیا وعدہ پورا کیا جارہا ہے۔ ساتھ ہی انہیں تجربہ کے سال کے حساب سے ویٹیج بھی دیا جارہا ہے۔ اگر کسی گیسٹ ٹیچر نے تعلیمی ٹرم 2012-13، 2013-14 اور 2014-15 کے دوران ہر ٹرم میں کم سے کم 120 دن تعلیمی کام کیا ہے اسے 2.25 فیصدی کا ویٹیج مل جائے گا۔

پہلا سال، بے مثال!

محلہ کلینک

پیرا گڑھی کے پنجابی باغ نئی آبادی بستی میں پہلا محلّہ کلینک شروع ہو گیا ہے۔ وہاں 200 مریض روز دیکھے جاتے ہیں۔ جنہیں ڈاکٹری صلاح و مشورہ، دوائیں اور جانچ سہولت مفت میں مہیا ہوتی ہے۔ براڑی اور منڈاولی میں بھی محلّہ کلینک بن کر تیار ہے۔ محلّہ کلینک صرف 20 لاکھ روپے کی لاگت سے بن کر تیار ہو رہے ہیں۔ دہلی میں 100 عام آدمی محلّہ کلینک کا ٹنڈر جاری ہو گیا ہے۔

ہیلتھ کارڈ

جلد ہی دہلی کے لوگوں کے ہیلتھ کارڈ بنیں گے۔ اس اسکیم کے تحت دہلی کے ہر شخص کی صحت سے متعلق ڈیٹا ریکارڈ کیا جائے گا۔ پورا ہیلتھ سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ ڈاکٹروں کو آسانی سے مریض کا ریکارڈ فوراً اپنے کمپیوٹر پر دِکھ جائے گا تو علاج میں آسانی ہوگی۔

بڑھیں گے مریضوں کے بیڈ

تمام اسپتالوں میں مریضوں کے بستروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ 2017 کے دسمبر تک دہلی کے اسپتالوں میں مریضوں کے لئے 20000 بیڈ دستیاب ہوں گے۔ یہ تعداد ابھی 10000 ہے۔ اس کے علاوہ 70 فیزیوتھراپی اور 250 ڈینٹل کلینک بھی کھولے جائیں گے۔

ڈاکٹروں کو راحت

ڈاکٹروں کو تمام سہولیات سے متعلق کام کی نگرانی بوجھ سے فری کیا جائے گا تا کہ وہ مریضوں کے علاج پر دھیان دے سکیں۔ اس کے لئے اسپتالوں میں منیجر مقرر کئے جائیں گے۔

پہلا سال، بے مثال!

نئی پائپ لائن

ایک سال میں دہلی میں 136 کلومیٹر نئی پائپ لائن بچھائی گئی۔ ساتھ ہی 148 کلومیٹر کی زنگ آلود پرانی پائپ لائن بدلی گئی تاکہ آلودہ پانی سپلائی نہ ہونے پائے۔ رساؤ روکنے کے لئے بھی خاص مہم چلائی گئی۔ پانی کی قلت والے علاقوں میں 78 اضافی ٹینکر لگائے گئے ہیں۔

سرکاری ٹیکس بڑھا

دہلی جل بورڈ کے صارفین کی تعداد بڑھ کر 19.58 لاکھ ہو چکی ہے۔ ہر مہینے 20 ہزار لیٹر مفت دینے کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے دہلی جل بورڈ کو اس سال فروری کے پہلے ہفتے تک 178 کروڑ روپے زیادہ سرکاری ٹیکس ملا۔

سدھرتی صحت...

دوا اور جانچ مفت

1 فروری 2016 سے دہلی کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو ساری دوائیں مفت مل رہی ہے۔ ڈاکٹر جو بھی دوا لکھتے ہیں انہیں ہر حال میں مہیا کرانا اسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس انتظام کی نگرانی اور دواؤں کی ہمیشہ مہیا کرانے کے لئے ایک موبائل ایپ بھی بنایا گیا ہے۔ ایکسرے اور الٹرا ساؤنڈ بھی مفت دستیاب ہے۔

پالی کلینک

دہلی کے بڑے اسپتالوں پر بوجھ ختم کرنے اور گھر کے آس پاس مریض کو وقت پر جانچ کرانے کی سہولت کے لئے دہلی کے الگ الگ علاقوں میں 22 پالی کلینک کھولے گئے ہیں۔ ہر کلینک میں اوسطاً 1200 مریض روز پہنچ رہے ہیں۔ سال کے آخر تک پوری دہلی میں ایسے 150 پالی کلینک شروع ہو جائیں گے۔

غیر منظور شدہ کالونیوں کو راحت دی گئی۔ واٹر ڈیولپمنٹ چارج کو 440 روپے ہر ایک مربع میٹر سے گھٹا کر 100 روپے ہر ایک مربع میٹر کر دیا گیا۔ اس سے 1.2 لاکھ لوگوں کو سیدھے فائدہ پہنچا۔ اس یوجنا کو اگلے چھ مہینے کے لئے پھر سے لاگو کر دیا گیا ہے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے ۔ غیر منظور شدہ کالونیوں میں سیور ڈیولپمنٹ چارج 494 روپے فی مربع میٹر کے حساب سے لیا جاتا تھا۔ اس میں قریب 80 فیصدی کی کمی کرتے ہوئے اسے 100 روپے فی مربع میٹر کر دیا گیا۔

اپنی پسند کی میٹر

طے معیاری پانی کے میٹر بیچنے کے لئے تین کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے۔ پانچ سال کی گارنٹی والے یہ نئے میٹر دھول، مٹی سے خراب نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی مرضی سے ان میں سے کسی بھی کمپنی کا میٹر خرید سکتے ہیں۔

کنکشن لینا سستا

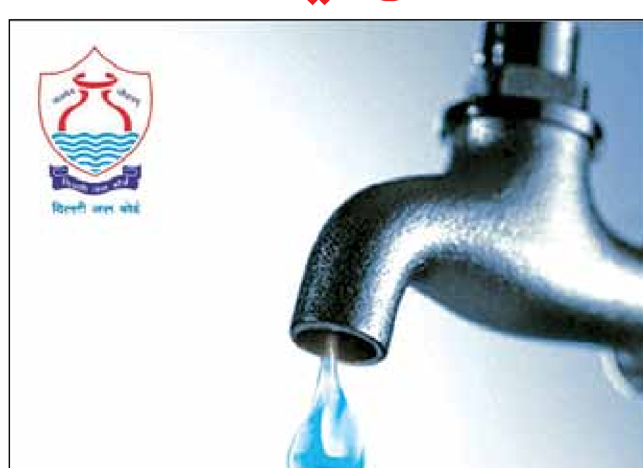

پانی کے غیر قانونی کنکشن کو قانونی کرنے کی نیتی نرم بنائی گئی ہے۔ پہلے اس کے لئے لوگوں کو 14000 روپے دینے پڑتے تھے۔ جسے گھٹا کر 3310 روپے کر دیا گیا۔ پانی کے محدود استعمال والے کمرشل ٹھکانوں کو گھریلو درجے میں لایا گیا۔

واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ

2011 میں بن کر تیار دوارکا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نے 1 مارچ 2015 سے کام کرنا شروع کر دیا۔ 50 ایم جی ڈی (ملین گیلن فی دن) صلاحیت والے اس پلانٹ کے شروع ہو جانے سے دوارکا نواحی، نجف گڑھ، دولت پور، اُجوا اور آس پاس کے علاقوں کے ساڑھے 13 لاکھ باشندگان کو فائدہ ہوا۔ 2002 میں بنے بوانا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نے 21 اپریل 2015 سے کام کرنا شروع کیا۔ 20 ایم جی ڈی صلاحیت والے اس پلانٹ سے بوانا، نریلا، سنلوتھ اور آس پاس کے گاؤں کے قریب چھ لاکھ باشندگان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اوکھلا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی صلاحیت 7 ایم جی ڈی سے 20 ایم جی ڈی ہوئی۔

پہلا سال، بے مثال!

رہی ہے۔اس کے قریب 50-60 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔اب تک ساؤتھ ایم سی ڈی علاقے میں 1.25 لاکھ اسٹریٹ لائٹ بدلی جا چکی ہیں۔

بجلی میٹر

بجلی میٹر کے تیز چلنے یا مضروب شدہ متعلقہ کوئی شکایت ہونے پر اب اس کی جانچ بجلی تقسیم کمپنیوں کی لیبارٹریوں میں نہیں ہوگی۔اب ان کی جانچ آزادانہ روپ سے این اے بی ایل سے تسلیم شدہ لیبارٹریوں میں کی جائے گی۔

بجھنے لگی پیاس...

پانی مفت

سرکار بننے کے فوراً بعد دہلی والوں سے مفت پانی کا وعدہ پورا کیا گیا۔ 1 مارچ 2015 سے ہر مہینے 20 ہزار لیٹر (قریب 700 لیٹر ہر دن) تک پانی کے استعمال پر کوئی قیمت نہیں لیا جا رہا ہے۔اس سے دہلی کی گروپ ہاؤسنگ سوسائٹیوں سمیت 8.99 لاکھ صارفین کو فائدہ ہوا ہے۔

کیا بل معاف

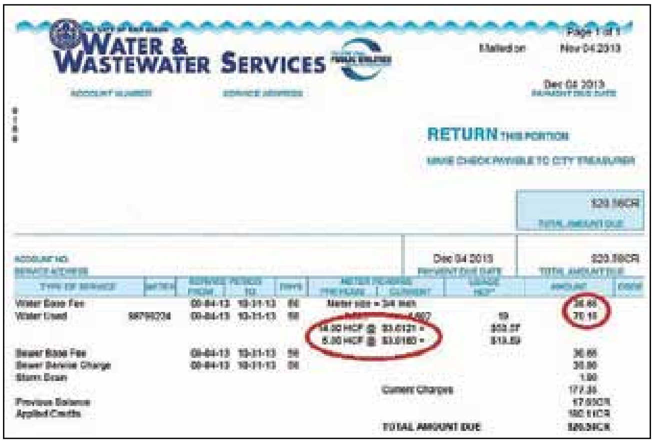

WATER & WASTEWATER SERVICES

Page 1 of 1

Mailed on Nov 04 2013

Dec 04 2013

RETURN THIS PORTION

Water Base Fee		09-04-13	10-31-13	58	Meter size = 3/4 inch			36.66
Water Used	98790234	09-04-13	10-31-13	58			19	70.15
					14.00 HCF @ $3.0121 =		$53.07	
					5.00 HCF @ $3.0180 =		$15.59	
Sewer Base Fee		09-04-13	10-31-13	58				36.66
Sewer Service Charge		09-04-13	10-31-13	58				38.90
Storm Drain								1.90
					Current Charges			177.36
Previous Balance								17.03CR
Applied Credits								180.11CR
					TOTAL AMOUNT DUE			$20.56CR

سرکار بننے کی پہلی سالگرہ پر 30 نومبر 2015 تک بقایا سبھی بلوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا گیا۔ان سبھی لوگوں کا بل معاف ہوا جن کے گھر پانی کے میٹر لگے ہوں گے اور وہ چالو حالت میں ہوں گے۔

غیر منظور شدہ کالونیوں کو راحت

اجالے کی جانب...

سستی بجلی

عام آدمی پارٹی کی سرکار بنتے ہی بجلی بل آدھے کرنے کا وعدہ پورا کیا گیا۔ 400 یونٹ تک ہر ایک ماہ بجلی کی استعمال کرنے والے سبھی صارفین کو یہ چھوٹ ملی۔ دہلی کے قریب 90 فیصدی بجلی صارفین کو اس یوجنا کا فائدہ ملا۔ سرکار نے اس کے لئے 1500 کروڑ روپے کی سبسڈی دی۔ دہلی سستی بجلی کے معاملے میں تیسرا سب سے سستا راجیہ ہے۔ یہی نہیں بجلی کمپنیوں کے دباؤ کے باوجود سرکار نے بجلی کی شرحوں میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے دی۔

لوڈ شیڈنگ بے حد کم

بجلی تقسیم قواعد کی ہمیشہ نگرانی کی گئی۔ اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ صرف 0.14 فیصدی رہ گئی۔ جو پچھلے سال کے مقابلے میں 73 فیصدی کم تھی۔ دہلی کی تاریخ میں اتنی کم لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوئی۔ دہلی والوں کو اس سے کافی راحت ملی۔ لوڈ شیڈنگ کی شکایت کے لئے 24 گھنٹے چلنے والا کال سینٹر قائم کیا گیا۔ بجلی تقسیم کمپنیوں (ڈسکامس) کو ہدایت دی گئی کہ کسی علاقے میں لوڈ شیڈنگ ایک وقت میں ایک گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ اور اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو وجہ عیاں کرتے ہوئے لوگوں کو وقت پر اس کی اطلاع دی جائے۔

سیٹلمنٹ اسکیم

متنازعہ بجلی بلوں کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ایک سیٹلمنٹ اسکیم شروع کی گئی۔ 30 اگست 2015 سے شروع ہوئی اس اسکیم سے اب تک 55000 سے زیادہ صارفین فائدہ اٹھا چکے ہیں۔

ایل ای ڈی بلب

توانائی بچاؤ مہم کے تحت دہلی میں 93 روپے کی در سے قریب 40 لاکھ ایل ای ڈی بلب تقسیم کئے گئے ہیں۔ تین سال کی گارنٹی والے ان بلب کے استعمال سے دہلی میں قریب 75 میگاواٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ کے موجودہ بلب بدل کر ایل ای ڈی بلب لگانے کی قواعد چل

پہلا سال، بے مثال!

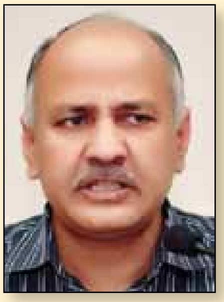

سوال: دہلی سب آرڈینیٹ سروسیز بورڈ (ڈی ایس ایس ایس بی) نے 2010 میں ہوئے ٹی جی ٹی (سوشل سائنس) کی امتحان کا نتیجہ بھی جاری نہیں کیا۔ کئی امیدوار اب زیادہ عمر حد پار کر گئے ہیں۔

منیش سسودیا (نائب وزیر اعلیٰ) بورڈ کے آفیسروں نے کہا ہے کہ اپریل تک نتیجہ آجائے گا۔ اس کے علاوہ مئی تک زیادہ تر نتیجے آجائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈی ایس ایس ایس بی کی امتحان اب آن لائن ہوں گے تاکہ جلد نتیجہ آجائے۔ نتیجہ آنے میں دیری کے چلتے سرکار کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسکولوں میں ٹیچروں کی ضرورت ہے۔ لیکن نتیجہ آنے میں دیری کے چلتے بھرتی نہیں ہو رہی ہے۔

سوال:۔ یمنا کو سیاحت سے جوڑنے کے لئے سرکار کی کیا اسکیم ہے؟

کپل مشرا (وزیر سیاحت) یمنا کو لے کر سرکار کئی طرح کی اسکیموں پر کام کر رہی ہے۔ یمنا کنارے جہاں جہاں صاف پانی ہے۔ وہاں پر بوٹنگ شروع کی گئی ہے۔ یمنا آرتی بھی شروع کی گئی ہے۔ آنے والے وقت میں یمنا کو یقینی طور پر سیاحت سے جوڑا جائے گا۔

سوال:۔ کھانے پینے میں ملاوٹ سے نپٹنے کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے؟

ستیندر جین (وزیر صحت) کھانے پینے میں ملاوٹ روکنے کے لئے سرکار عالمی سطح کی لیباریٹری بنانے جا رہی ہے۔ مہم چلا کر لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل فوڈ سیفٹی لیب میں کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کو پکڑا جائے گا۔ عام آدمی سرکار بننے کے بعد سے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ کے تحت کھاد بیوپاریوں کو لائسنس اور رجسٹریشن دینے کی قواعد میں کافی تیزی آئی ہے۔ نئی لیباریٹریوں میں جدید سہولتیں ہوں گی اور اونچی سطح کی ٹیسٹ کئے جائیں گے۔ اس کے کھانے۔ پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کو آسانی سے پکڑا جا سکے گا۔ ابھی موجودہ لیباریٹریاں اتنی کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔

سوال:۔ عام آدمی کینٹین کی تجویز کہاں تک پہنچی ہے؟

آشیش کھیتان (وائس چیئر مین: دہلی ڈائیلاگ کمیشن) دہلی ڈائیلاگ کمیشن نے عام آدمی کینٹین کی پالیسی طے کی ہے۔ اس سال کے آخر تک 70 سے 80 کینٹین شروع ہو جائے گی۔ دہلی یونیورسٹی علاقے میں بھی کینٹین ہوں گی۔ ایک ساتھ بڑے پیمانے پر کینٹین شروع ہوں گی۔

پہلا سال، بے مثال!

14 فروری 2016 کو این ڈی ایم سی کنونشن سینٹر میں وزیر اعلیٰ عوام کو اپنی سرکار کا حساب دینے پہنچے۔ انہوں نے صاف کہا کہ عوام ووٹ دے کر مالک نہیں خدمتگار چنتی ہے۔ اسے خدمتگار سے حساب لینے کا پورا حق ہے۔ سیوک کا بھی فرض ہے کہ وہ مالک کو وقت وقت پر اپنے کام کاج کا لیکھا جوکھا دے۔ انہوں نے خوشی کے موقع پر 30 نومبر تک پانی کے بقایا بلوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔

اس موقع پر کیجریوال اور ان کے وزیروں نے عوام کے سوالوں کا سیدھا جواب دیا۔ اس کے لئے کچھ فون نمبر تھے جن پر لوگوں نے سوال پوچھا اور کیجریوال وان کے وزیروں نے جواب دیئے۔ کچھ چنے ہوئے سوال پیش ہیں:۔

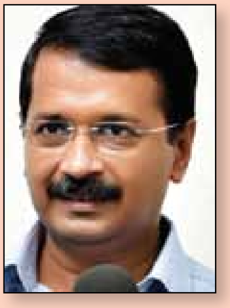

سوال:۔ بدعنوانی کے ایک معاملے میں اے سی بی کو شکایت کی تھی۔ لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پولیس بھی کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ اگر عام آدمی پارٹی سرکار کا نام لیتے ہیں، تو پولیس اور بھڑک جاتی ہے۔

اروند کیجریوال (سی ایم): بدقسمتی پولیس اور اے سی بی دونوں ہی دہلی سرکار کے تحت نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنی شکایت کی کاپی دیجئے۔ اس کی شکایت کو وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے پاس بھیجوں گا اور کارروائی کی مانگ کروں گا۔ دہلی اسمبلی نے جن لوک پال بل پاس کر دیا ہے۔ اور یہ بل مرکز کے پاس ہے۔ اگر مرکز منظوری دے دے تو پھر اس طرح کی شکایتوں سے آسانی سے نپٹا جا سکے گا۔

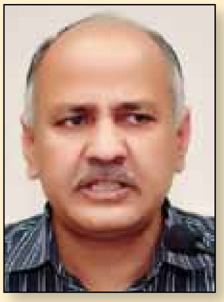

سوال:۔ آپ سرکار نے 500 نئے اسکول شروع کرنے کی بات کہی تھی۔ اس مسئلے پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟

منیش سسودیا (نائب وزیر اعلیٰ) اس سال 25 نئے اسکول شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 200 اسکولوں کے بنیادی سہولتوں کے لئے 8000 نئے کلاس روم بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 100 نئے اسکولوں کے لئے زمین تلاشی گئی ہے۔ جہاں جہاں پر نئے اسکولوں کے لئے زمین مل رہی ہے۔ وہاں پر نئے اسکول بنائے جائیں گے۔

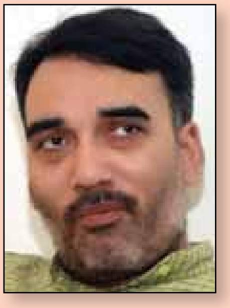

سوال:۔ طاق و جفت اسکیم کو لے کر کیا تجربہ رہے؟

گوپال رائے (وزیر ٹرانسپورٹ) طاق و جفت اسکیم کا استعمال کئی ملکوں میں کیا گیا تھا لیکن وہاں پر یہ مہم مقبول نہیں ہو پائی۔ دہلی میں عوام نے اس مہم کو بہت پسند کیا اور اب 15 اپریل سے پھر سے یہ مہم شروع کی جا رہی ہے۔ طاق و جفت اسکیم کے دوران جہاں آلودگی سطح میں 20 سے 24 فیصد تک کی کمی آئی وہیں دہلی والوں کو جام سے بھی نجات ملی۔

کیجریوال کی ’خدمتگار سرکار‘ کا

ایک سال، بے مثال !

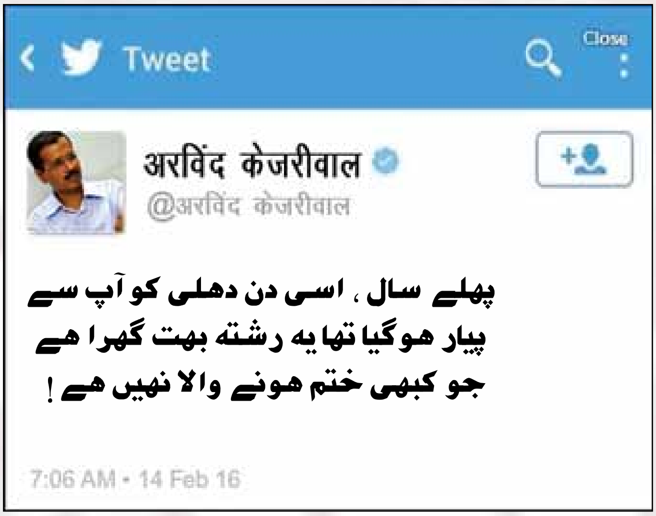

14 فروری 2015 کو پورے ملک میں ایک چمتکار ثابت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔عام لوگوں کے آندولن سے سیاسی جماعت میں تبدیل ہوئی ایک پارٹی بے مثال اکثریت (70 میں 67 سیٹ جیت کر) کے ساتھ سرکار بنا رہی تھی۔اروند کیجریوال وزیر اعلیٰ عہدہ کی حلف لے رہے تھے تو رام لیلا میدان میں اتساہ اور اُمنگ لہریں لے رہا تھا۔اروند کیجریوال نے دہلی کے لوگوں کے بھروسے پر کھرا اترنے کیلئے رات دن محنت کی اور جب پہلے سال کا حساب دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس گنانے کیلئے ایسا بہت کچھ تھا جسے دیکھ کر عوام نے بہت پیار سے کہا- **کیجریوال بے مثال !**

होली मुबारक

चलो, फागुन की खुशियाँ मनाएं !

आज पीले हैं सरसों के खेत, लो;
आज किरणें हैं कंचन समेट, लो;
आज कोयल बहन हो गई बावली

उसकी कुहू में अपनी लड़ी गीत की हम मिलाएं !

आज अपनी तरह फूल हंसकर जगे,
आज आमों में भौंरों के गुच्छे लगे,
आज भौंरों के दल हो गए बावले

उनकी गुनगुन में अपनी लड़ी गीत की हम मिलाएं !

आज नाची किरण, आज डोली हवा!
आज फूलों के कानों में बोली हवा
उसका सन्देश फूलों से पूछें, चलो
और कुहू करें गुनगुनाए !

चलो, फागुन की खुशियाँ मनाएं !!

।। भवानी प्रसाद मिश्र ।।

क्योंकि अब दिल्ली में है
ईमानदार सरकार

दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में सारी दवाइयां और टेस्ट हुए फ्री

- ☑ दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में सारी दवाइयां और टेस्ट - सब फ्री कर दिये हैं। पहले होता था कि डॉक्टर 10 दवाइयां लिखता था तो एक दवाई खिड़की पर मिलती थी बाकी कहते थे कि बाहर से ले लो। हमने सारे अस्पतालों को पूरा पैसा दिया है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी दवाइयां अब अस्पताल में मिलें, चाहे कोई दवाई कितनी भी महंगी हो। अस्पतालों पर नज़र भी रख रहे हैं कि कोई दवाई चोरी न हो। इसके अलावा सारे टेस्ट भी फ्री कर दिये। जैसे पहले अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह के पैसे लगते थे। अब सब फ्री हो गये।
- ☑ दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिये
- ☑ लोगों के पानी के पुराने बिल माफ़ कर दिये
- ☑ जब किसानों की फसल बर्बाद हुई तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति किल्ले मुआवज़ा दिया
- ☑ दिल्ली में 1000 नई डिस्पेंसरी बन रही हैं, नये स्कूल बन रहे हैं।

आम आदमी सरकार के पास इतने पैसे कहां से आते है?

लोग अचंभा कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार के पास इतना पैसा कहां से आता है? बाकी पार्टियां तो कहती रहती हैं पैसे नहीं हैं। हम बताते है कि पैसे कहां से आते हैं। अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है। हम हर सरकारी काम में खूब पैसे बचा रहे हैं। जैसे-

- ☑ 325 करोड़ का एक पुल बनना था, हमने उसे 200 करोड़ में बना दिया। 125 करोड़ बचा लिए एक पुल में।
- ☑ पहले एक डिस्पेंसरी 5 करोड़ में बनती थी, हम 20 लाख में बनाते हैं एक डिस्पेंसरी।
- ☑ एक आई.टी.आई बनना था 24 करोड़ का, हमने उसे 16 करोड़ में बना दिया। 8 करोड़ बचा लिए उस आई.टी.आई में।

ईमानदारी से काम हो रहा है। हर सरकारी काम में खूब पैसे बच रहे हैं। उसी से आपको इतना फायदा हो रहा है।

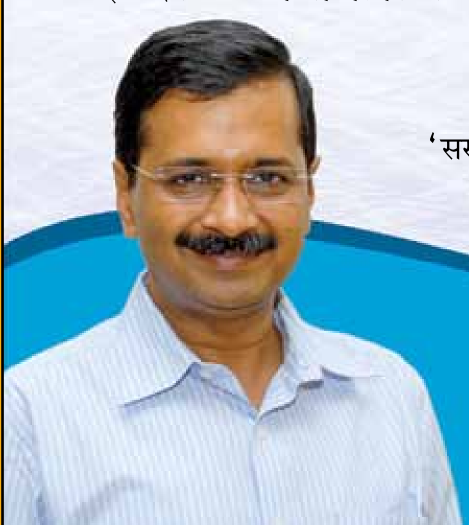

'सरकार में पैसे की कमी नहीं है। नीयत की कमी थी। अब दिल्ली में साफ़ नीयत की सरकार है। अब जनता के सारे काम हो रहे हैं।'

- अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

श्री सज्जन सिंह यादव, निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित एवं आकांक्षा इम्प्रेशन्स, 18/36 स्ट्रीट नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-05 द्वारा मुद्रित